दिव्य हिमगिरि

हिमालयी राज्यों की पहली साप्ताहिक पत्रिका

नज़र सब पर

15th ANNIVERSARY

वर्ष 15 | अंक 35 | मूल्य 05 रुपये | 18-24 जनवरी, 2026

10 मिनट डिलीवरी का कल्चर खत्म

उत्तराखंड में भूमि विवादों का अब होगा त्वरित निस्तारण

किसान आत्महत्या मामले में पुलिस की लापरवाही पर सीएम धामी का सख्त एक्शन

EXPERIENCE HELI TOUR WITH

Himgiri Aviation & Tourism

SINCE 2018

A Unit of दिव्य हिमगिरि

5N/6D TOUR

Chardham

YATRA BY HELICOPTOR

ADVANCE BOOKING STARTS

BOOK NOW

POSSIBLE OPENING DATES

Yamnotri	19 April, 2026
Gangotri	19 April, 2026
Kedarnath	22 April, 2026
Badrinath	24 April, 2026

Contact for Reservation 8433456398, 9410353164

Email: himgiritourism@gmail.com

6 Municipal Road, Opp. Oxford School of Excellence, Dalanwala, Dehradun-248001 (UK)

वर्ष 15 | अंक 35

दिव्य हिमगिरि

18-24 जनवरी, 2026

संपादक
डॉ. कुँवर राज अस्थाना

वरिष्ठ संवाददाता
शंभूनाथ गौतम

संवाददाता
पूनम आर्या

विज्ञापन
सुनील सेमवाल

ग्राफिक डिजायनर
देव भट्ट

संवाददाता
हरिद्वार: डॉ. रजनीश गौतम
पौडी: रत्नमणि भट्ट
कोटद्वार: के.पी. बौंठियाल
रूद्रपुर: हेमचन्द्र बुडलाकोटी
चमोली: मुकेश रावत
रुड़की: श्रीगोपाल नारसन
नैनीताल: शीतल तिवारी
अल्मोड़ा: संजय कुमार अग्रवाल (एड.)
विकासनगर: अजय शर्मा
प्रसार: रमेश सिंह रावत

संपादकीय कार्यालय : 6, म्युनिसिपल रोड, बाला हिसार स्कूल के सामने, डालनवाला देहरादून (उत्तराखंड)
मोबाइल : +91 8433456398, 9410353164
Email: divyahimgiriddn@gmail.com

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक कुँवर बहादुर अस्थाना द्वारा आईशा प्रिंटिंग प्रेस, 292/1, चुक्खूवाला, ओंकार रोड, देहरादून-248001 उत्तराखण्ड से प्रकाशित।
संपादक: कुँवर बहादुर अस्थाना*

*(पीआरबी एक्ट के तहत प्रकाशित सामग्री के लिए उत्तरदायी)

क्या बेरोजगारी रोक रही विकसित भारत की राह

देश में पिछले कुछ वर्षों से बेरोजगारी एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। इससे बड़े स्तर पर युवा श्रम शक्ति का इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है और यह राष्ट्र के संपूर्ण विकास में भी अवरोध पैदा कर रहा है। किसी भी अर्थव्यवस्था को तभी संतुलित माना जाता है, जब उसमें आर्थिक विकास के साथ-साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हों। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कुल कार्यबल तथा जनसंख्या के लिहाज से भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश है। यहां युवाओं की आबादी अन्य देशों की तुलना में अधिक है। मगर इस कार्यबल को व्यापक रूप से राष्ट्र के निर्माण में भागीदारी के समान अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। इसका आकलन केंद्रीय सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से गुरुवार को जारी रपट से किया जा सकता है। इसमें कहा गया है कि देश में पंद्रह वर्ष और उससे अधिक उम्र के लोगों के बीच बेरोजगारी दर पिछले वर्ष दिसंबर में बढ़कर 4.8 फीसद पर पहुंच गई, जबकि नवंबर में यह आंकड़ा 4.7 फीसद था। शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी का असर ज्यादा रहा, जहां इसकी दर नवंबर में 6.5 फीसद से बढ़कर 6.7 फीसद हो गई। इससे स्पष्ट है कि सरकारी और निजी संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में रोजगार के अवसर घट रहे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार की ओर से 'आत्मनिर्भर भारत' और 'स्किल इंडिया' जैसी योजनाओं की शुरुआत की गई है, लेकिन इनका असर विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग रहा है। कई युवा और श्रमिक वर्ग अपने कौशल को विकसित करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, इसके बावजूद उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। कृत्रिम मेधा और डिजिटलीकरण के कारण भी रोजगार में कमी आई है। हालांकि, डिजिटल क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं, लेकिन इनमें भी विशेष कौशल की आवश्यकता होती है, जो हर किसी के पास नहीं है। इसमें दोराय नहीं कि रोजगार की मांग के अनुपात में सरकारी नौकरियों की संख्या में वृद्धि नहीं हो पा रही है। इसके अलावा, सरकारी भर्ती प्रक्रियाओं में देरी और परीक्षा प्रणाली के मुद्दे भी रोजगार हासिल करने के समान अवसरों को प्रभावित करते हैं। हालांकि आंकड़ों के हिसाब से देखें तो शहरों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में राहत की बात यह है कि वहां पिछले वर्ष नवंबर से दिसंबर के बीच बेरोजगारी दर 3.9 फीसद पर स्थिर है। दरअसल, किसी भी देश में संपूर्ण आर्थिक विकास तभी संभव हो पाता है, जब सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि हो, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी तथा गरीबी, भुखमरी और सामाजिक असमानता में कमी आए तथा रोजगार की उपलब्धता और प्रति व्यक्ति खुशहाली हो। विकास का मॉडल ऐसा होना चाहिए, जिसमें रोजगार के अवसर, गरीबों का उत्थान और किसानों की समृद्धि सुनिश्चित हो सके तथा महंगाई की दर कम रहे। सवाल है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत का जो लक्ष्य रखा है, क्या मौजूदा परिस्थितियों की लिहाज से उसे तय समय में हासिल किया जा सकेगा! यह सच है कि बेरोजगारी दर में उतार-चढ़ाव से देश के विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि बेरोजगारी दर में कमी लाने के लिए शिक्षा को कौशल विकास से जोड़ने को प्राथमिकता दी जाए और सरकारी एवं निजी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित किए जाएं तभी भारत सही मायने में एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ पाएगा।

डॉ. कुँवर राज अस्थाना

विद्यालयी शिक्षा को सशक्त और कोचिंग को अनावश्यक बनाना वर्तमान जरूरत

डॉ. ओंकार सिंह

हाल ही में एक समिति की रिपोर्ट को लेकर व्यापक चर्चा हो रही है, जिसमें स्कूली छात्रों के लिए कोचिंग के घंटो की सीमा तय करने, स्कूल पाठ्यक्रम को उच्च शिक्षा में प्रवेश हेतु होने वाली प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के अनुरूप ढालने, तथा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए बोर्ड परीक्षा के अंकों को अधिक महत्व देने जैसे सुझाव दिए गए हैं। इन प्रस्तावों पर विचार करते समय यह समझना आवश्यक है कि समस्या की जड़ स्कूल शिक्षा की समग्र गुणवत्ता, बोर्ड परीक्षाओं की विश्वसनीयता और कोचिंग पर बढ़ती निर्भरता में छिपी है। स्कूल शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए सभी पहलुओं पर ईमानदार और आलोचनात्मक आत्ममंथन जरुरी है, न कि यथास्थिति को स्वीकार कर तात्कालिक बदलाव करना, जिनके दीर्घकालिक दुष्परिणाम हो सकते हैं।

समानांतर चलती स्कूलिंग और कोचिंग

प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्रणाली समय की जरूरतों के अनुरूप स्वाभाविक रूप से विकसित हुई है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर नियामक संस्थाएं पाठ्यक्रम की निरंतर समीक्षा करती रहती है, ताकि भारतीय स्कूलों से निकलने वाले छात्र किसी भी तरह से कमजोर न हो। यह भी सच है कि भारत की स्कूल शिक्षा व्यवस्था वैश्विक मानकों की है- कई देशों से बेहतर- फिर भी दशकों से कोचिंग का समानांतर तंत्र फल-फूल रहा है।

कोचिंग का समानांतर शिक्षा व्यवस्था के रुप में उभरना इस बात का संकेत है कि स्कूल, हितधारको की अपेक्षाओं को पूरा करने में कहीं न कहीं चूक रहे हैं। कोचिंग लेने वाले छात्रों को धन, समय और श्रम-तीनों का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ता है। यानी कोचिंग उनकी पसंद नहीं, बल्कि मजबूरी बन गई है, क्योंकि स्कूल आवश्यक शैक्षणिक योगदान देने में असफल रहे हैं। खासकर जैईइी, नीट जैसी प्रवेश परीक्षाओं में सफलता के लिए कोचिंग को अनिवार्य मान लेने की धारणा ने विद्यालयी शिक्षा में छात्रों की गंभीर भागीदारी को कमजोर किया है। नतीजतन, छात्र प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी में कोचिंग पर अधिक समय देते हैं, और स्कूल का पाठ्यक्रम व बोर्ड परीक्षाएं महज पास होने तक सीमित रह जाती हैं। इसी प्रवृत्ति ने 'डमी स्कूलों' को जन्म दिया है, जहां छात्र केवल बोर्ड परीक्षा में बैठते हैं और वास्तविक पढाई की पूरी जिम्मेदारी कोचिंग संस्थान निभाते हैं।

कोचिंग के लिए अधिकतम अवधि तय करने जैसे प्रस्ताव अनजाने में कोचिंग को अनिवार्य ठहरा सकते हैं और स्कूलिंग को और कमजोर कर सकते हैं। ऐसे में जरुरत इस बात की है कि स्कूलों की शिक्षण-अधिगम-मूल्यांकन प्रक्रियाओं की गुणवत्ता को समग्र रूप से मजबूत किया जाए, ताकि कोचिंग हाशिए पर चली जाए। इससे छात्रों और अभिभावको दोनों को बड़ी राहत मिलेगी।

निसंदेह, स्कूल शिक्षा में अपेक्षित सुधारों के लिए विषय विशेषज्ञों द्वारा शिक्षको का निरंतर प्रशिक्षण, उत्साही और सक्षम शिक्षकों का निर्माण, तथा उन्हें उचित वेतन और सेवा शर्तें देना अनिवार्य है। बहुत कम वेतन पर बड़ी संख्या में संविदा तथा अस्थायी शिक्षको की नियुक्ति से स्कूल शिक्षा सशक्त नहीं हो सकती। बच्चों को उच्च शिक्षा या जीवन के लिए तैयार करने में स्कूल शिक्षकों की भूमिका को देखते हुए शिक्षा व्यवस्था को अस्थायी और संविदा नियुक्तियो से मुक्त कर, शीघ्र ही जवाबदेही सुनिश्चित करनी होगी।

पाठ्यक्रम और स्कूल के बाद की प्रवेश परीक्षाएं

पाठ्यक्रम के संदर्भ में भारत में एक सुदृढ़ नियामक ढांचा है, जो निर्धारित सहभागी प्रक्रिया के तहत पाठ्यक्रम तैयार करता है। यह समझना जरूरी है कि उच्च शिक्षा के कार्यक्रम स्कूल शिक्षा में दी गई आधारभूत दक्षताओं पर ही निर्मित होते हैं। प्रवेश परीक्षाओं की भूमिका केवल योग्य उम्मीदवारों में से मेरिट के आधार पर चयन करना है। ऐसे में कुछ चुनिंदा प्रवेश परीक्षाओं के अनुरुप स्कूल पाठ्यक्रम में बदलाव करना उचित नहीं लगता। इससे स्कूल के बाद सीखने में खालीपन पैदा होगा और दीर्घकालिक नुकसान होगा।

इसके बजाय, आवश्यकता पड़ने पर प्रवेश परीक्षाओं की विषयवस्तु को अर्हकारी कक्षा के स्कूल पाठ्यक्रम तक सीमित रखा जाना चाहिए। किसी छात्र की पात्रता का निर्धारण स्कूल की निर्धारित कक्षा उत्तीर्ण करने से होता है, न कि प्रवेश परीक्षा में प्रदर्शन से।

असल बात यह है कि यदि विभिन्न विद्यालयी परीक्षा बोर्डों की परीक्षाएं विश्वसनीय, सुसंगत और मानक के अनुरूप होती, तो उच्च शिक्षा में प्रवेश के लिए

अलग से प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं की जरूरत ही नहीं पड़ती। सभी उच्च शिक्षा कार्यक्रमों में बोर्ड अंकों के आधार पर प्रवेश की व्यवस्था से छात्रों में प्रवेश परीक्षा का भय भी कम होगा और वे स्कूल की पढ़ाई और परीक्षाओं पर बेहतर ध्यान दे सकेंगे।

यह स्वीकार करना होगा कि धीमी गति से सीखने वाले छात्रों या विशेष दक्षताएं हासिल करने के इच्छुक छात्रों के लिए ट्यूशन या कोचिंग को पूरी तरह समाप्त करना संभव नहीं है। लेकिन यह धारणा कि कोचिंग अनिवार्य है-इसे जरूर बदला जाना चाहिए। एमसीक्यू आधारित प्रवेश परीक्षाओं के पैटर्न और उनकी तैयारी स्कूलों में ही कराई जा सकती है, यदि शिक्षक कोचिंग पर निर्भरता कम करने का संकल्प लें। स्कूल प्रशासन संबंधित कक्षाओं में इसकी योजना बना सकता है, उच्च शिक्षा के इच्छुक छात्रों को परामर्श दे सकता है और उनकी समग्र क्षमताओं को निखार सकता है।

आगे की राह

यह अच्छी बात है कि कोचिंग और स्कूल शिक्षा को लेकर बहस शुरु हुई है और स्कूलों से अपेक्षा की जा रही है कि वे अपनी शिक्षण प्रक्रियाओं में सुधार करें, ताकि बड़ी संख्या में छात्रों के लिए कोचिंग अनावश्यक हो जाए। स्कूल शिक्षा नियामकों, शिक्षाविदों और प्रशासन को कक्षा शिक्षण की गुणवत्ता बढ़ानी होगी और बोर्ड परीक्षाओं की कठोरता को सुदृढ करना होगा, ताकि इन परीक्षाओं की गंभीरता बनी रहे और स्कूली शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो।

यह नहीं भूलना चाहिए कि स्कूल शिक्षा का पाठ्यक्रम ही मूल आधार है. जिस पर उच्च शिक्षा के विभिन्न पाठ्यक्रम निर्मित होते हैं। इसलिए प्रवेश परीक्षाओं को आसान बनाने या छात्रों को कोचिंग से दूर करने के लिए पाठ्यक्रम में जल्दबाजी में किए गए बदलाव, बिना दीर्घकालिक प्रभावो पर विचार किए, नहीं होने चाहिए। सरकार स्तर पर तत्काल ही कोचिंग और डमी स्कूलों के वर्तमान स्वरुप पर प्रभावी रोक लगाने का ठोस निर्णय इस दिशा में एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है।

लेखक के बारे में:
डॉ. ओंकार सिंह, वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून (उत्तराखंड) के पूर्व कुलपति हैं। वे मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) के संस्थापक कुलपति भी रहे है।

हाई वैल्यू फसलों के उत्पादन और प्रसंस्करण से प्रदेश के किसानों की आर्थिकी में बेहतर सुधार हो सकता हैः मुख्य सचिव

मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने किया सगंध पौधा केंद्र का भ्रमण

मुख्य सचिव ने सगन्ध पौधा केन्द्र द्वारा प्रदेश के किसानों को डोर स्टेप सहायता उपलब्ध कराए जाने के दिए निर्देश

मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन ने जनपद देहरादून के सेलाकुई में स्थित सगन्ध पौधा केन्द्र का भ्रमण किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने सगन्ध पौधा केन्द्र द्वारा किए जा रहे कार्यों की विस्तार से जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हाई वैल्यू फसलों के उत्पादन और प्रसंस्करण से प्रदेश के किसानों की आर्थिकी में बेहतर सुधार हो सकता है। उन्होंने सगन्ध पौधा केन्द्र द्वारा प्रदेश के किसानों को डोर स्टेप सहायता उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने इसके लिए सगन्ध पौधा केन्द्र को और मजबूत किए जाने पर जोर दिया, ताकि सगन्ध पौधा केन्द्र प्रदेशभर में अपनी गतिविधियों को बढ़ा सके।

मुख्य सचिव ने सभी जनपदों में उनकी जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप एरोमैटिक फसलों का चयन कर प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को इसमें जोड़े जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि किसानों को सगन्ध फसलों के उत्पादन में अपेक्षित सहयोग उपलब्ध कराया जाए। साथ ही उन्होंने 6 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में तैयार किए जा रहे सैटेलाईट सेंटर्स को भी शीघ्र शुरू किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने परफ्यूमरी एंड ऐरोमैटिक सेक्टर में उच्च शिक्षा एवं कौशल विकास के अंतर्गत डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेशन कार्यक्रम संचालित किए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने अपने पूर्व में दिए निर्देशों को दोहराते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को जनपदों में भ्रमण कर समीक्षा कर फीडबैक लेने के लिए लगातार दौरे करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने निर्देश दिए कि अन्य विभागों द्वारा संचालित फल एवं सब्जियों से जुड़े आजीविका की योजनाओं को भी इसमें शामिल किया जाए। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक किसान इस सगन्ध पौध उत्पादन और प्रसंस्करण कार्य से जुड़ें इसके लिए सभी जनपदों में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएं। उन्होंने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए वार्षिक कार्ययोजना जनवरी माह तक पूर्ण किए जाने की बात दोहराते हुए कहा कि निर्धारित अवधि में कार्य पूर्ण हो सकें इसके लिए जनपदों के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किए जाएं। इस अवसर पर निदेशक सगन्ध पौधा केन्द्र डॉ. निर्पेंद्र चौहान ने बताया कि सगन्ध पौधा केन्द्र को खुशबूदार फसलों के वाणिज्यीकरण के लिए एक सफल मॉडल के रूप में विकसित किया है, जो एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। उन्होंने कहा कि यह एक बिजनेस इनक्यूबेटर के तौर पर काम करता है, जो किसानों, उद्यमियों और एसेंशियल ऑयल इंडस्ट्री को सपोर्ट देता है।

किसान आत्महत्या मामले में पुलिस की लापरवाही पर सीएम धामी का सख्त एक्शन

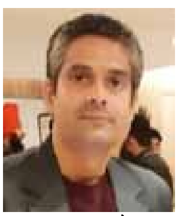

शंभू नाथ गौतम
वरिष्ठ पत्रकार

हल्द्वानी के गौलापार स्थित होटल में 11 जनवरी को 40 वर्षीय किसान सुखवंत सिंह ने आत्महत्या कर ली थी, जिसमें उन्होंने फेसबुक लाइव के जरिए आरोप लगाया था कि उनके साथ 26 लोगों ने करीब चार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की और वह कई बार पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा चुके थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस घटना ने न सिर्फ स्थानीय लोगों को हिला कर रख दिया, बल्कि पूरे प्रदेश में गहरी संवेदना और आक्रोश भी पैदा कर दिया। किसान ने अपने फेसबुक लाइव में सीधे एसएसपी समेत कई पुलिस कर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए और मरने से पहले अपने कनपट्टी पर गोली मार ली। घटना के तुरंत बाद उत्तराखंड पुलिस प्रशासन में हलचल मच गई। एसएसपी ने कोतवाल और संबंधित एसआई को सस्पेंड करते हुए पूरी पैगा चौकी को लाइन हाजिर कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर मामले की निष्पक्ष जांच के लिए तत्काल उच्च स्तरीय एसआईटी गठित की गई। इस गंभीर प्रकरण में पुलिस मुख्यालय ने 12 पुलिसकर्मियों को ऊधमसिंह नगर से हटाकर गढ़वाल रेंज के चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में ट्रांसफर कर दिया, ताकि जांच प्रभावित न हो और पारदर्शिता बनी रहे। इसमें आईटीआई थानाध्यक्ष, दरोगा और सिपाही सहित कई वरिष्ठ पुलिसकर्मी शामिल हैं। डीजीपी दीपम सेठ ने बताया कि सुखवंत ने आत्महत्या से पहले प्रदेश के आला अधिकारियों को एक ई-मेल भेजा था, जिसमें स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों के नाम लिखकर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे।

हल्द्वानी के गौलापार स्थित होटल में 11 जनवरी को 40 वर्षीय किसान सुखवंत सिंह ने अपनी जान दे दी। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में उन्होंने फेसबुक लाइव के माध्यम से आरोप लगाए कि उनके साथ 26 लोगों ने चार करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी की है। उन्होंने बताया कि वह कई बार पुलिस प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों से इंसाफ मांगते रहे, लेकिन किसी ने उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। इस फेसबुक लाइव में उन्होंने सीधे एसएसपी समेत कई पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। कुछ ही मिनटों के भीतर उन्होंने अपने कनपट्टी पर गोली मार ली, और इस घटना ने न केवल उनके परिवार और गांव को सदमे में डाल दिया, बल्कि पूरे प्रदेश को भी हिला कर रख दिया। स्थानीय लोग और किसान संगठनों ने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया। उनका कहना था कि यह केवल एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि किसानों के साथ हो रही लगातार लापरवाही और न्यायिक अक्षमता की शर्मनाक तस्वीर पेश करता है। कई लोग सड़क पर उतर आए और प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की। सोशल मीडिया पर भी लोग इस घटना पर गहरी संवेदना और आक्रोश व्यक्त कर रहे थे। घटना के तुरंत बाद पुलिस प्रशासन ने कार्रवाई शुरू की। पैगा चौकी के कोतवाल और संबंधित एसआई को सस्पेंड कर दिया गया और पूरी चौकी को लाइन हाजिर कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए। एसआईटी का नेतृत्व आईजी एसटीएफ नीलेश आनंद भरणे करेंगे, और इसमें एसपी

चम्पावत अजय गणपति, सीओ टनकपुर वंदना वर्मा, निरीक्षक दिवान सिंह बिष्ट, एसआई मनीष खत्री सहित कई वरिष्ठ अधिकारी शामिल हैं। एसआईटी को यह जिम्मेदारी दी गई कि वह मामले की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच करे। पुलिस की लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस मुख्यालय ने 12 पुलिसकर्मियों को ऊधमसिंह नगर से हटाकर गढ़वाल रेंज के चमोली और रुद्रप्रयाग जिलों में ट्रांसफर कर दिया। इनमें आईटीआई थानाध्यक्ष रहे दरोगा कुंदन सिंह रौतेला, दरोगा प्रकाश बिष्ट, हेड कांस्टेबल शेखर बनकोटी, सिपाही भूपेंद्र सिंह, दिनेश तिवारी, सुरेश चंद्र, दरोगा जितेंद्र कुमार, एएसआई सोमवीर सिंह, सिपाही योगेश चौधरी, राजेंद्र गिरी, दीपक प्रसाद और संजय कुमार शामिल हैं। यह कदम जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने और प्रभावित न होने देने के लिए उठाया गया है। डीजीपी दीपम सेठ ने बताया कि सुखवंत ने आत्महत्या से पहले प्रदेश के आला अधिकारियों और विभिन्न विभागों को ई-मेल भेजा था। इसमें उन्होंने स्थानीय लोगों और पुलिस अधिकारियों पर कई गंभीर आरोप लिखे थे। ई-मेल में 17 अटैचमेंट थे और इसे 30 ई-मेल आईडी पर सीसी किया गया था। एसआईटी ने इस ई-मेल की भी गहन पड़ताल शुरू कर दी है। उनका कहना था कि इस जांच में हर पहलू की जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह घटना पुलिस की लगातार लापरवाही और किसानों के साथ हो रही न्यायिक अक्षमता का प्रतीक है। कई किसानों ने बताया कि सुखवंत कई बार प्रशासन के पास इंसाफ की गुहार लेकर गए थे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। एसआईटी की जांच से पहले ही लोगों में सरकार से अपेक्षाएं बढ़ गई हैं कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। प्रदेश सरकार का यह कदम पुलिस में अनुशासन बनाए रखने और किसानों के मामलों में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और एसआईटी की जांच पूरी पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ होगी। स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया पर इस घटना की व्यापक चर्चा हो रही है। किसान संगठनों और नागरिकों का कहना है कि सुखवंत की आत्महत्या ने पुलिस की लापरवाही और प्रशासन की निष्क्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एसआईटी जांच की निगरानी के लिए उच्च स्तर पर निर्देश दिए गए हैं कि दोषियों को किसी भी हालत में बख्शा न जाए और कार्रवाई समयबद्ध तरीके से पूरी की जाए। इस मामले में एसआईटी जांच की शुरूआत के साथ ही पूरे प्रदेश में अधिकारियों और पुलिसकर्मियों में अलर्ट मोड सक्रिय हो गया है। अधिकारी इस मामले में हर छोटे से छोटे तथ्य की जांच कर रहे हैं, जिसमें किसान द्वारा भेजे गए ई-मेल, स्थानीय शिकायतें, पुलिस रिपोर्ट और फेसबुक लाइव वीडियो शामिल हैं। एसआईटी ने यह भी निर्देश दिए हैं कि कोई भी संबंधित पुलिसकर्मी जांच में हस्तक्षेप न कर सके। यह प्रकरण किसानों के अधिकार, प्रशासन की जवाबदेही और पुलिस की निष्पक्षता के महत्व को उजागर करता है। प्रदेश में यह उम्मीद जताई जा रही है कि एसआईटी की जांच से दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी और भविष्य में किसानों के मामलों में न्यायिक प्रक्रिया में तेजी और पारदर्शिता आएगी।

नियमों को ताक पर रखकर इंस्पेक्टर की कुर्सी पर बैठाया गया दरोगा, पुलिस व्यवस्था की खुली पोल

काशीपुर क्षेत्र के किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के बाद उधमसिंह नगर पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह मामला अब केवल एक किसान की मौत तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पुलिस विभाग में लंबे समय से चल रहे अटैचमेंट और पदस्थापना के खेल को उजागर करता दिखाई दे रहा है। आत्महत्या प्रकरण सामने आने के बाद काशीपुर चौकी और आईटीआई कोतवाली की भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं। आरोप है कि शुरुआती दौर में मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। इसी बीच यह तथ्य सामने आया कि आईटीआई कोतवाली में इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी निभा रहे अधिकारी कुंदन रौतेला मूल रूप से दरोगा हैं, जिनका वेतन बागेश्वर जनपद से आहरित होता है, जबकि उनकी तैनाती उधमसिंह नगर में की गई है। दरोगा कुंदन रौतेला के खिलाफ पूर्व में शिकायतें और एफआईआर दर्ज रही हैं। इन शिकायतों के बावजूद उन्हें बागेश्वर से अटैच कर उधमसिंह नगर लाया गया और नियमों को दरकिनार करते हुए आईटीआई कोतवाली में इंस्पेक्टर की कुर्सी सौंप दी गई। यह पूरा मामला पुलिस विभाग की आंतरिक व्यवस्था, नियमों की अनदेखी और जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। किसान सुखवंत सिंह की मौत के बाद इलाके में आक्रोश का माहौल है। सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय जांच की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते शिकायतों पर कार्रवाई होती और नियमों के अनुसार अधिकारियों की तैनाती की जाती, तो यह दुखद घटना शायद टाली जा सकती थी। मामले को लेकर आईजी कुमाऊं रिद्धिम अग्रवाल ने कहा कि किसान आत्महत्या प्रकरण को गंभीरता से लिया गया है। पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। यदि जांच में किसी स्तर पर नियमों का उल्लंघन या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अटैचमेंट और तैनाती की प्रक्रिया की भी समीक्षा की जा रही है। वहीं एसएसपी उधमसिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने कहा कि आत्महत्या मामले की जांच निष्पक्ष तरीके से की जा रही है। सभी तथ्यों और पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। इस पूरे मामले पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था की विफलता को दर्शाती है। नियमों को ताक पर रखकर अधिकारियों की तैनाती की जा रही है और शिकायतों के बावजूद कार्रवाई नहीं होती। इस पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए।

किसान आत्महत्या मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ होगी सख्त कार्रवाईः सीएम धामी

ऊधमसिंह नगर जनपद के काशीपुर निवासी किसान द्वारा हल्द्वानी में आत्महत्या किए जाने के गंभीर प्रकरण को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अत्यंत संवेदनशीलता से लेते हुए कुमाऊं आयुक्त दीपक रावत द्वारा मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा है कि इस दुखद घटना के सभी तथ्यों और परिस्थितियों की निष्पक्ष एवं पारदर्शी जांच सुनिश्चित की जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके और यदि किसी स्तर पर लापरवाही

यशपाल आर्य ने राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन पर साधा निशाना

किसान की आत्महत्या के मामले में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि प्रदेश की कानून-व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है। उत्तराखंड पुलिस आज अपनी मूल जिम्मेदारी, कानून की रखवाली छोड़कर जमीन और सत्तासंरक्षित लेन-देन के कारोबार में उलझ गई है। इसका भयावह उदाहरण काशीपुर से सामने आया, जहां किसान सुखवंत सिंह ने न्याय न मिलने की पीड़ा में वीडियो जारी कर अपने जीवन का अंत कर लिया। आर्य ने इस घटना को केवल एक व्यक्तिगत त्रासदी नहीं बताया बल्कि इसे व्यवस्था के नैतिक पतन और सरकार की नाकामी का जीवंत प्रमाण कहा। उनका कहना था कि यह वारदात प्रदेश में व्याप्त भ्रष्ट और असंतुलित कानून-व्यवस्था का सबूत है। नेता प्रतिपक्ष ने बताया कि सुखवंत सिंह ने अपने वीडियो में स्पष्ट रूप से कहा कि उनके साथ चार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी हुई। जब उन्होंने न्याय की आस लेकर थाने का रुख किया, तो आरोप है कि थाना प्रभारी और एसपी स्तर तक के पुलिस अधिकारियों ने शिकायत सुनने के बजाय पैसों के लालच में दूसरे पक्ष का साथ दिया। पीड़ित को डराया-धमकाया गया, बार-बार थाने बुलाकर प्रताड़ित किया गया और आखिरकार पूरी तरह हताश कर दिया गया। यशपाल आर्य ने कहा कि यह घटना किसी एक थाने या जिले की नहीं है, बल्कि पूरे प्रशासन की कार्यशैली और उत्तराखंड पुलिस के गिरते भरोसे पर तमाचा है। उन्होंने चेताया कि प्रदेश भय, अन्याय और असुरक्षा की ओर बढ़ रहा है और वही चेतावनी अब एक मौत के रूप में सामने आई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सत्ता में बैठे लोग चाहे स्थायी हों या अस्थायी, लेकिन अन्याय का हिसाब इतिहास जरूर लेता है। आर्य ने कहा कि सुखवंत सिंह की आत्महत्या पूरी घटना उत्तराखंड सरकार और पुलिस प्रशासन के माथे पर कलंक है और दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना आवश्यक है।

या दोष पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा सके। मुख्यमंत्री धामी ने इस संबंध में मुख्य सचिव आनंद बर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ से भी पूरे प्रकरण की विस्तृत जानकारी ली है। मुख्यमंत्री धामी ने दिवंगत किसान के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार इस कठिन समय में परिवार के साथ खड़ी है। उन्होंने प्रशासन को निर्देश दिए कि पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जाए तथा उन्हें न्याय दिलाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं।

किसान आत्महत्या मामले में कांग्रेस नेताओं ने किया धरना प्रदर्शन

उत्तराखंड में किसान सुखवंत सिंह की आत्महत्या के मामले ने पूरे प्रदेश में संवेदनशील स्थिति पैदा कर दी। इस गंभीर प्रकरण को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य और कांग्रेस नेता गणेश गोदियाल ने मंगलवार को काशीपुर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने पुलिस की लापरवाही और सरकार की निष्क्रियता पर तीखा हमला करते हुए कहा कि यह केवल एक व्यक्तिगत घटना नहीं है, बल्कि पूरे प्रदेश में कानून-व्यवस्था की विफलता और किसानों के साथ हो रहे अन्याय का प्रतीक है। धरने के दौरान नेताओं ने कहा कि सुखवंत सिंह ने अपने फेसबुक लाइव वीडियो और ई-मेल के जरिए पुलिस और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन ने समय पर कार्रवाई नहीं की। उन्होंने दोषियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई की मांग की। यशपाल आर्य ने चेताया कि राज्य में लगातार बढ़ते अन्याय और भय के माहौल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। धरने में स्थानीय लोग और किसान संगठन भी शामिल हुए। उन्होंने सरकार से न्याय दिलाने और भविष्य में किसानों के मामलों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की अपील की। प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से हुआ, लेकिन इसमें सरकार और पुलिस प्रशासन के प्रति नाराजगी साफ झलक रही थी।

सेब, कीवी और ड्रैगनफ्रूट की उत्पादकता बढ़ाने हेतु कार्ययोजना बनाई जाएः मुख्य सचिव

मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में सेब की अति सघन बागवानी योजना सम्बन्ध में शासन में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने प्रदेश में सेब, कीवी और ड्रैगनफ्रूट का उत्पादन बढ़ाए जाने के सम्बन्ध में अधिकारियों से चर्चा की। मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता एवं अन्य राज्यों की उत्पादन क्षमता के सापेक्ष उत्तराखण्ड की उत्पादन क्षमता पर विस्तार से चर्चा की। मुख्य सचिव ने कहा कि "सेब की अति सघन बागवानी योजना" के अंतर्गत सेब की नवीनतम प्रजातियों के बागान स्थापित करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्य करने की आवश्यकता है। इसके लिए मुख्य सचिव ने जनपदों में किसानों को क्लस्टर बेस्ड एप्रोच अपनाए जाने हेतु प्रेरित किया जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस योजना का उद्देश्य राज्य में सेब उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। प्रदेश में अभी सेब उत्पादन क्षेत्र बढ़ाए जाने की अत्यधिक सम्भावना है, जो प्रदेश में सेब, कीवी और ड्रैगनफ्रूट उत्पादन की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम साबित होगा। मुख्य सचिव ने सेब, कीवी और ड्रैगनफ्रूट की उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रदेश की उत्पादन क्षमता विशेषकर सेब की उत्पादन क्षमता का आंकलन किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनपदों को सेब उत्पादन में क्षमता के अनुरूप 2030, 2040 एवं 2050 में कितना उत्पादन होगा, इसके लिए उत्पादन लक्ष्य निर्धारित करते हुए योजना को धरातल पर उतारा जाए। मुख्य सचिव ने कहा कि झाला (हर्षिल, उत्तरकाशी) स्थिति कोल्ड स्टोरेज की तर्ज पर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी कोल्ड स्टोरेज तैयार किए जाएं। इससे किसान अपना सेब और अन्य उत्पाद ऑफ सीजन में मार्केट में उतार कर अधिक लाभ ले सकेंगे। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रदेश के अधिकतम क्षेत्रों में अभी भी पुरानी कम उत्पादन क्षमता वाली किस्म की फसलों का उत्पादन हो रहा है। उन्हें हाई डेंसिटी ऐपल प्लांट्स से रिप्लेस करने की आवश्यकता है। उन्होंने किसानों से संवाद करने के निर्देश प्रदान किए।

10 मिनट डिलीवरी का कल्चर खत्म

शहरों की तेज रफ्तार जिंदगी में सुविधा की अंधी दौड़ ने इंसानी जान को हाशिये पर ला दिया था। मोबाइल स्क्रीन पर दौड़ता टाइमर, पीठ पर भारी बैग और सिर पर "10 मिनट डिलीवरी" का दबाव डिलीवरी राइडर्स हर दिन सड़कों पर अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे थे। लेकिन अब इस खतरनाक रफ्तार पर सरकार ने निर्णायक हस्तक्षेप करते हुए साफ लगाम लगा दी है। केंद्र सरकार के निर्देश के बाद क्विक-कॉमर्स कंपनियों ने सख्त डिलीवरी टाइम लिमिट हटाने पर सहमति जता दी है और 10 मिनट डिलीवरी जैसी ब्रांडिंग को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यह फैसला सिर्फ एक कारोबारी बदलाव नहीं, बल्कि यह संदेश है कि अब सुविधा और मुनाफे से ऊपर इंसानी जीवन और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। यह कदम उन लाखों गिग वर्कर्स के लिए बड़ी राहत है, जो अब बिना डर और दबाव के सुरक्षित तरीके से काम कर सकेंगे। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट।

शहरों की तेज होती जिंदगी में सुविधा की होड़ ने जिस तरह डिलीवरी राइडर्स की जान को जोखिम में डाल दिया था, उस पर अब केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बाद ठोस बदलाव साफ दिखाई देने लगा है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय की सख्त सलाह के बाद क्विक-कॉमर्स कंपनियों ने '10 मिनट डिलीवरी' जैसे दावों को हटाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। सरकार का साफ संदेश था कि तेज डिलीवरी का दबाव राइडर्स की सुरक्षा से बड़ा नहीं हो सकता और किसी भी हाल में इंसानी जान को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद सबसे पहले ब्लिंकिट ने अपने प्लेटफॉर्म से '10 मिनट डिलीवरी' का दावा हटा दिया है। कंपनी ने अपने ऐप, विज्ञापनों और ब्रांडिंग से वह टैगलाइन हटाई, जो ग्राहकों के साथ-साथ राइडर्स पर भी समय का जबरदस्त दबाव बनाती थी। ब्लिंकिट का यह कदम साफ तौर पर यह संकेत देता है कि सरकार की चेतावनी को अब केवल औपचारिक नहीं, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी लागू किया जा रहा है। लंबे समय से यह आरोप लगता रहा है कि 10 मिनट में डिलीवरी का वादा राइडर्स को तेज रफ्तार, जोखिम भरी ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी के लिए मजबूर करता है। ब्लिंकिट के बाद जेप्टो और स्विगी इंस्टामार्ट ने भी '10 मिनट डिलीवरी' जैसी ब्रांडिंग को हटाने या उसमें बदलाव करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि वे अब अपनी मार्केटिंग और प्रचार सामग्री में सख्त समय-सीमा वाले वादों से दूरी बना रही हैं। हालांकि कंपनियों का यह भी कहना है कि उनकी डिलीवरी सेवा पहले की तरह तेज बनी रहेगी, लेकिन अब इसे किसी तय मिनट की सीमा से नहीं जोड़ा जाएगा। इसका उद्देश्य यह बताया गया है कि डिलीवरी पार्टनर्स पर अनावश्यक मानसिक और शारीरिक दबाव न पड़े। जोमैटो, जो ब्लिंकिट की पैरेंट कंपनी है, ने भी यह स्वीकार किया है कि राइडर्स की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और भविष्य में किसी भी तरह की ब्रांडिंग या फीचर में ऐसा कोई तत्व नहीं होगा, जिससे डिलीवरी कर्मियों पर असुरक्षित तरीके से काम करने का दबाव बने। इसी तरह स्विगी ने भी संकेत दिए हैं कि वह अपने प्लेटफॉर्म पर डिलीवरी टाइम को लेकर भाषा और प्रस्तुति में बदलाव कर रही है, ताकि ग्राहकों की अपेक्षाएं यथार्थपरक हों और राइडर्स सुरक्षित तरीके से काम कर सकें। सरकार का मानना है कि '10 मिनट डिलीवरी' जैसे दावे सिर्फ मार्केटिंग टूल नहीं थे, बल्कि वे सड़कों पर दौड़ते हजारों राइडर्स के लिए एक अदृश्य खतरे की तरह काम कर रहे थे। मोबाइल स्क्रीन पर चलता काउंटडाउन टाइमर, ग्राहक की उम्मीदें और ऐप की रेटिंग प्रणाली, इन सबका बोझ अंततः राइडर के कंधों पर आ जाता था। कई मामलों में यह दबाव दुर्घटनाओं, चोटों और कभी-कभी जानलेवा हादसों का कारण भी बना। यही वजह है कि श्रम मंत्रालय ने कंपनियों को साफ तौर पर चेताया कि यदि सुरक्षा को नजरअंदाज किया गया, तो सख्त नियामक कदम उठाए

आप सांसद राघव चड्डा ने '10 मिनट डिलीवरी' मामले को संसद में उठाया था

राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्डा ने गिग वर्कर्स, खासकर डिलीवरी राइडर्स और क्विक-कॉमर्स कर्मचारियों के अधिकारों और सुरक्षा को लेकर मुद्दा सबसे पहले संसद में जोरदार तरीके से उठाया था। दिसंबर सत्र में उन्होंने '10 मिनट डिलीवरी' जैसे समय-सीमा वाले वादों को "क्रूर और जोखिम भरा" बताते हुए इसका कड़ा विरोध किया और सरकार से इसे रोकने की मांग की। उन्होंने सदन के जीरो ऑवर में कहा कि जब उपभोक्ता 10 मिनट में डिलीवरी चाहते हैं, तो कानून गोपनीय रूप से यह भी जान ले कि "डिलीवरी पार्टनर इंसान हैं, मशीन नहीं" और उनकी सुरक्षा, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। चड्डा ने संसद में यह भी स्पष्ट किया कि डिलीवरी राइडर्स के पास अक्सर न तो पेंशन, न सामाजिक सुरक्षा और न ही सम्मानजनक वेतन होता है, जबकि वे "भारत की अर्थव्यवस्था की अदृश्य कड़ी" हैं। उन्होंने तर्क दिया कि '10 मिनट डिलीवरी' का दबाव राइडर्स को नियमों का उल्लंघन, तेज रफ्तार, रात भर काम और असुरक्षित स्थितियों में जाने के लिए मजबूर करता है, जिससे उनकी जान को खतरा होता है।

जा सकते हैं। इस फैसले का गिग वर्कर्स संगठनों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह पहली बार है जब सरकार ने डिजिटल इकॉनमी में काम करने वाले गिग वर्कर्स की जमीनी सच्चाई को इतनी गंभीरता से लिया है। डिलीवरी राइडर्स लंबे समय से यह मांग कर रहे थे कि उनसे तेजी की अपेक्षा तो की जाती है, लेकिन उनकी सुरक्षा, बीमा और काम के हालात पर उतना ध्यान नहीं दिया जाता। अब '10 मिनट डिलीवरी' जैसे दबाव हटने से उन्हें उम्मीद है कि काम का माहौल थोड़ा सुरक्षित और मानवीय बनेगा। राजनीतिक स्तर पर भी इस फैसले को समर्थन मिला है। हाल के दिनों में गिग वर्कर्स के मुद्दे को मुखर रूप से उठाने वाले नेताओं का कहना है कि यह कदम केवल डिलीवरी राइडर्स के लिए ही नहीं, बल्कि सड़कों पर चलने वाले हर नागरिक की सुरक्षा के लिए जरूरी था। तेज डिलीवरी की होड़ में न सिर्फ राइडर्स, बल्कि पैदल चलने वाले और अन्य वाहन चालक भी जोखिम में पड़ जाते थे। अब जब कंपनियां इस होड़ से पीछे हट रही हैं, तो इसका सकारात्मक असर सड़क सुरक्षा पर भी देखने को मिल सकता है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद क्विक-कॉमर्स सेक्टर में एक अहम बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। ब्लिंकिट द्वारा '10 मिनट डिलीवरी' का दावा हटाना और जेप्टो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म्स द्वारा इसी दिशा में कदम बढ़ाना यह दिखाता है कि अब मुनाफे और सुविधा से ऊपर इंसानी जीवन को रखा जा रहा है। आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि क्या यह बदलाव सिर्फ ब्रांडिंग तक सीमित रहता है या वास्तव में गिग वर्कर्स के काम के हालात, सुरक्षा और सम्मान में भी ठोस सुधार लेकर आता है। फिलहाल इतना साफ है कि रफ्तार की इस अंधी दौड़ पर अब लगाम लग चुकी है और गिग वर्कर्स के लिए एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद जगी है।

उपनल कर्मचारियों के खिले चेहरे, समान वेतन का रास्ता साफ

वर्षों से समान काम के बदले कम वेतन और असुरक्षित भविष्य की पीड़ा झेल रहे उपनल कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिए गए ऐतिहासिक फैसले ने हजारों उपनल कर्मियों की उम्मीदों को नई उड़ान दी है। धामी सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में वर्ष 2015 से पहले से लगातार सेवाएं दे रहे उपनल कर्मचारियों को अब समान कार्य के बदले समान वेतन का लाभ मिलेगा। इस निर्णय से न केवल लंबे समय से चले आ रहे असंतोष का समाधान होगा, बल्कि उपनल कर्मियों के मन में यह भरोसा भी मजबूत होगा कि सरकार उनकी मेहनत और योगदान को गंभीरता से समझती है। कैबिनेट का यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है, जिन्होंने वर्षों तक विभागों में अपनी सेवाएं दीं, लेकिन वेतन और सुविधाओं के मामले में पीछे रह गए। पहले जहां यह लाभ 12 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को देने का निर्णय था, वहीं धामी सरकार ने उपनल कर्मियों के हित में इसे घटाकर 10 वर्ष कर दिया। धामी सरकार के इस फैसले से करीब सात से आठ हजार उपनल कर्मचारियों को जल्द लाभ मिलने का रास्ता साफ हुआ है। दिव्य हिमगिरि रिपोर्ट।

उत्तराखंड में वर्षों से उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में सेवाएं दे रहे हजारों कर्मचारियों के लिए आखिरकार राहत की बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में उपनल कर्मियों के हित में एक अहम और दूरगामी फैसला लिया गया है। इस निर्णय के तहत वर्ष 2015 से पहले से लगातार सेवाएं दे रहे उपनल कर्मचारियों को समान कार्य के बदले समान वेतन दिया जाएगा। सरकार के इस फैसले से लंबे समय से वेतन असमानता और भविष्य की अनिश्चितता से जूझ रहे कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है। अब तक उपनल कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग यही रही है कि उन्हें उनके कार्य के अनुरूप सम्मानजनक वेतन मिले। कई कर्मचारी एक ही विभाग में वर्षों से नियमित कर्मचारियों के समान जिम्मेदारियां निभा रहे थे, लेकिन वेतन और सुविधाओं में बड़ा अंतर बना हुआ था। इस असमानता को दूर करने के लिए धामी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने पहले वर्ष 2025 में 12 वर्ष की सेवा पूरी करने वालों को यह लाभ देने का निर्णय लिया था, लेकिन कर्मचारियों की भावनाओं और जमीनी हालात को देखते हुए इसे घटाकर 10 वर्ष कर दिया गया है। इससे अधिक संख्या में उपनल कर्मियों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए सचिव मुख्यमंत्री शैलेश बगौली ने बताया कि समान कार्य समान वेतन का लाभ चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। पहले चरण में प्रदेश के विभिन्न विभागों में वे सभी उपनल कर्मी शामिल होंगे, जो वर्ष 2015 या उससे पहले से लगातार सेवाएं दे रहे हैं और जिनकी 10 वर्ष की सेवा 2025 में पूरी हो रही है। सभी संबंधित विभाग इन कर्मियों के साथ अलग-अलग अनुबंध करेंगे और इसकी प्रक्रिया दो माह के भीतर पूरी की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि इस फैसले का लाभ समय पर कर्मचारियों तक पहुंचे और किसी तरह की अनावश्यक देरी न हो। धामी सरकार के इस फैसले से करीब सात से आठ हजार उपनल कर्मियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। ये वे कर्मचारी हैं, जिन्होंने

लंबे समय तक सीमित संसाधनों और कम वेतन में भी सरकारी तंत्र को सुचारु रूप से चलाने में अहम भूमिका निभाई है। विभागों में लिपिकीय कार्य, तकनीकी सहायता, कार्यालय संचालन और फील्ड स्तर के कई कार्य उपनल कर्मियों के भरोसे ही चलते रहे हैं। ऐसे में सरकार द्वारा उनकी सेवाओं को मान्यता देना और उन्हें आर्थिक राहत देना एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कैबिनेट बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि भविष्य में उपनल के माध्यम से केवल पूर्व सैनिकों और उनके स्वजनों को ही रोजगार दिया जाएगा। अन्य श्रेणी के कर्मचारियों के लिए अलग एजेंसी के चयन की प्रक्रिया जल्द पूरी की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे भर्ती व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी और विभिन्न वर्गों के लिए स्पष्ट नीति तय होगी। साथ ही इससे उपनल की मूल भावना को भी मजबूती मिलेगी, जो पूर्व सैनिकों के पुनर्वास से जुड़ी रही है। उपनल कर्मचारियों के संगठनों ने धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यह निर्णय वर्षों से चली आ रही मांग को पूरा करने की दिशा में बड़ा कदम है। कर्मचारियों को उम्मीद है कि इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि उन्हें सामाजिक सम्मान और कार्यस्थल पर स्थिरता भी मिलेगी। कई कर्मचारियों ने इसे सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच का परिणाम बताया है। उपनल कर्मियों को समान कार्य समान वेतन देने का यह फैसला धामी सरकार की कर्मचारी हितैषी नीति को दर्शाता है। यह निर्णय न केवल हजारों परिवारों के जीवन में आर्थिक राहत लाएगा, बल्कि राज्य के प्रशासनिक तंत्र में भरोसा और संतुलन भी मजबूत करेगा। आने वाले समय में जब यह फैसला पूरी तरह लागू होगा, तब उपनल कर्मचारियों के लिए यह एक नए अध्याय की शुरुआत साबित हो सकता है।

उपनल कर्मियों ने मुख्यमंत्री धामी का जताया आभार

धामी कैबिनेट में गुरुवार को उपनल कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है। जिसके बाद उपनल कर्मचारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उपनलकर्मियों ने समान काम के लिए समान वेतन के संबंध में कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसले के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार व्यक्त किया। उपनल कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री धामी से कहा कि यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही उनकी मांगों को पूरा करने के साथ-साथ उनके सम्मान और आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस फैसले से प्रदेश के हजारों उपनल कर्मचारियों में उत्साह एवं विश्वास का वातावरण बना है। सीएम धामी ने कहा कि राज्य सरकार उपनलकर्मियों के हितों की रक्षा, उनके सम्मान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है। उपनल कर्मचारी राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण कड़ी हैं। उनके योगदान को सरकार पूरी गंभीरता से मान्यता देती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश सरकार कर्मचारियों के कल्याण से जुड़े सभी मुद्दों पर संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है।उपनल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि वे सरकार की नीतियों और निर्णयों के अनुरूप पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। उपनल कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर *'समान कार्य समान वेतन'* संबंधी कैबिनेट के ऐतिहासिक निर्णय के लिए आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर उपनल कर्मचारी महासंघ, उत्तराखंड के अध्यक्ष विनोद गोदियाल, प्रदेश महामंत्री विनय प्रसाद, मौजूद थे।

यूएसडीएमए की कार्यप्रणाली से रूबरू हुए प्रशिक्षु डिप्टी एसपी

आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका पर प्रदान की गई जानकारी

उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (यूएसडीएमए) में वर्ष 2024 बैच के प्रशिक्षु डिप्टी पुलिस अधीक्षक राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली, संस्थागत ढांचे तथा आपदा प्रबंधन के विभिन्न चरणों में पुलिस के अधिकारियों तथा विभाग की भूमिका से रूबरू हुए। इस दौरान प्रशिक्षु अधिकारियों को आपदा प्रबंधन विभाग की कार्यप्रणाली, आईआरएस (इंसिडेंट रिस्पॉन्स सिस्टम) की अवधारणा एवं संरचना, चेतावनी प्रसारण तंत्र, आपदा पूर्व तैयारी, आपदा के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया तथा आपदा उपरांत पुनर्वास एवं पुनर्निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका, नीतिगत दिशा-निर्देशों तथा राज्य स्तर पर उनके क्रियान्वयन की प्रक्रिया पर भी प्रकाश डाला गया। अधिकारी एसईओसी और डीईओसी की कार्य प्रणाली से भी रूबरू हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सचिव आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास श्री विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपदा प्रबंधन के संपूर्ण चक्र-आपदा पूर्व, आपदा के दौरान एवं आपदा के बाद की प्रक्रिया में पुलिस विभाग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील होती है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपदा की स्थिति में पुलिस बल सबसे पहले मौके पर पहुंचने वाले प्रमुख एजेंसियों में से एक होता है, जिसकी जिम्मेदारी केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रहती, बल्कि मानव जीवन की सुरक्षा, त्वरित राहत एवं बचाव कार्यो में सक्रिय सहयोग देना भी होती है। उन्होंने बताया कि आपदा के समय पुलिस की प्रमुख भूमिका में प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित पहुंच सुनिश्चित करना, सुरक्षित निकासी (एवैक्यूएशन), भीड़ एवं यातायात प्रबंधन, राहत सामग्री के निर्बाध वितरण में सहयोग, संवेदनशील स्थलों की सुरक्षा, अफवाहों पर नियंत्रण तथा सटीक सूचना का संप्रेषण शामिल है। इसके अतिरिक्त प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य, अग्निशमन, एसडीआरएफ एवं अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर संयुक्त रूप से प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करना भी पुलिस की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु अधिकारियों को भविष्य में एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी के रूप में आपदा प्रबंधन से जुड़ी रणनीतिक एवं नेतृत्वकारी भूमिकाओं का निर्वहन करना होगा।

उत्तराखंड में भूमि विवादों का अब होगा त्वरित निस्तारण

उत्तराखंड में वर्षों से लंबित भूमि विवादों से जूझ रहे हजारों लोगों के लिए अब बड़ी राहत की खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सख्त निर्देशों के बाद सरकार ने भूमि से जुड़े मामलों के त्वरित और प्रभावी समाधान की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आमजन की परेशानी, आपसी तनाव और कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अब जमीन के झगड़े फाइलों में नहीं, बल्कि तय समय-सीमा में निपटाए जाएंगे। इसके तहत सभी जिलों में एक माह का विशेष अभियान चलाकर लंबित भूमि विवादों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जाएगा, ताकि लोगों को जल्द न्याय मिले और प्रशासन पर भरोसा और मजबूत हो। शंभू नाथ गौतम

उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जमीन केवल संपत्ति नहीं, बल्कि लोगों की पहचान, सम्मान और पीढ़ियों की मेहनत का प्रतीक होती है। यहां की हर इंच भूमि से किसी न किसी परिवार की आजीविका, भावनाएं और भविष्य जुड़ा है। लेकिन वर्षों से राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भूमि से जुड़े विवाद आम लोगों के लिए सबसे बड़ी परेशानी बने हुए हैं। कहीं सीमांकन को लेकर झगड़ा है, तो कहीं कब्जे, पैतृक बंटवारे, चकबंदी या सरकारी अभिलेखों में त्रुटियों के कारण लोग सालों से तहसील, थाना और अदालतों के चक्कर काटने को मजबूर हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए एक माह का विशेष अभियान चलाने का फैसला उन हजारों परिवारों के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर सामने आया है, जो लंबे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे थे। उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी जमीन ही जीवन का आधार है। खेती-किसानी, मकान, पशुपालन और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य इसी पर टिका होता है। कई परिवार ऐसे हैं जिनकी पूरी जिंदगी की कमाई एक छोटे से भूखंड में लगी हुई है। लेकिन जब उसी जमीन पर विवाद खड़ा हो जाता है, तो न सिर्फ आर्थिक नुकसान होता है, बल्कि परिवारों के बीच तनाव, गांवों में आपसी रंजिश और सामाजिक सौहार्द भी प्रभावित होता है। छोटे-छोटे विवाद कई बार बड़े झगड़ों का रूप ले लेते हैं और मामला पुलिस तथा अदालत तक पहुंच जाता है। इससे आम आदमी का समय, पैसा और मानसिक शांति तीनों छिन जाते हैं। मुख्यमंत्री धामी ने इस सच्चाई को गंभीरता से समझते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि भूमि विवादों को अब टालने या लटकाने की नीति नहीं चलेगी। उन्होंने मुख्य सचिव आनंद बर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को निर्देश दिए हैं कि राज्य के सभी जनपदों में लंबित भूमि विवादों की पहचान कर एक माह के भीतर उनका निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री का यह निर्देश केवल प्रशासनिक आदेश नहीं, बल्कि उन पीड़ित लोगों के दर्द को समझने का प्रयास है, जो वर्षों से अपने ही हक की जमीन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस विशेष अभियान का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि सरकार ने इसका लक्ष्य बेहद स्पष्ट रखा है, अभियान के अंत तक भूमि विवादों से जुड़े लंबित मामलों को शून्य स्तर तक लाना। यह लक्ष्य बताता है कि सरकार आधे-अधूरे समाधान से संतुष्ट नहीं होना चाहती, बल्कि जमीनी स्तर पर वास्तविक राहत देना चाहती है। मुख्यमंत्री ने यह भी साफ कर दिया है कि अभियान के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसका सीधा संदेश अधिकारियों तक जाता है कि आम जनता की समस्या को प्राथमिकता पर लिया जाए। भूमि विवादों का प्रभाव केवल व्यक्तिगत स्तर तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इससे कानून-व्यवस्था भी प्रभावित होती है। कई बार जमीन के झगड़े हिंसा, मारपीट और लंबे कानूनी विवाद का कारण बन जाते हैं। मुख्यमंत्री ने इस पहलू को ध्यान में रखते हुए प्रशासन और पुलिस के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया है। तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियों के गठन का निर्देश इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इन समितियों में पुलिस और चकबंदी विभाग के अधिकारियों को शामिल करने से यह सुनिश्चित होगा कि प्रशासनिक, राजस्व और पुलिस तीनों स्तर पर एक साथ काम हो और विवादों का समाधान तेजी से निकले। उत्तराखंड के दूरस्थ पर्वतीय इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह फैसला और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। पहाड़ी क्षेत्रों में तहसील और जिला मुख्यालय तक पहुंचना आसान नहीं होता। कई बुजुर्ग, महिलाएं और किसान केवल एक सुनवाई के लिए लंबी दूरी तय करते हैं। कई बार खराब मौसम, सड़कें बंद होने और संसाधनों की कमी के कारण उनकी सुनवाई टल जाती है। ऐसे में यदि विवादों का निस्तारण स्थानीय स्तर पर, तय समय-सीमा में हो जाए, तो यह आम लोगों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इस अभियान की नियमित समीक्षा का जिम्मा मुख्य सचिव को दिया जाना भी सरकार की गंभीरता को दर्शाता है। साप्ताहिक समीक्षा से यह सुनिश्चित होगा कि कहीं कोई मामला अनावश्यक रूप से लंबित न रहे और जरूरत पड़ने पर तुरंत सुधारात्मक कदम उठाए जाएं। इससे न केवल अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी, बल्कि आम जनता में भी यह विश्वास पैदा होगा कि उनकी शिकायतों को सुना जा रहा है। भूमि विवादों से परेशान लोगों के लिए यह फैसला इसलिए भी भावनात्मक महत्व रखता है क्योंकि कई मामलों में विवाद पीढ़ियों से चला आ रहा होता है। पिता के बाद बेटा और फिर पोता उसी जमीन के लिए लड़ता रहता है। ऐसे मामलों में केवल कानूनी समाधान ही नहीं, बल्कि संवेदनशील और मानवीय दृष्टिकोण की भी जरूरत होती है। मुख्यमंत्री द्वारा संवेदनशील मामलों पर विशेष ध्यान देने का निर्देश इसी सोच को दर्शाता है। सरकार यह

देहरादून समेत कई जिलों में भूमि विवादों के मामलों में लगातार दर्ज हो रही बढ़ोतरी

हाल के वर्षों में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून समेत राज्य के कई जिलों में भूमि विवादों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शहरीकरण, तेजी से बढ़ते रियल एस्टेट कारोबार, आबादी के दबाव और भूमि के बढ़ते दामों ने जमीन से जुड़े विवादों को और जटिल बना दिया है। देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी जैसे जिलों में भूमि विवाद अब आम लोगों की सबसे बड़ी समस्याओं में शामिल हो गए हैं। देहरादून में बाहरी निवेश और तेजी से हो रहे निर्माण कार्यों के कारण जमीन की मांग लगातार बढ़ रही है। इसके चलते सीमांकन, कब्जे, फर्जी दस्तावेज, बैनामा विवाद और सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। कई इलाकों में पुराने राजस्व अभिलेखों और मौजूदा रिकॉर्ड में अंतर होने से विवाद और गहरे हो गए हैं। स्थिति यह है कि छोटी-सी जमीन को लेकर परिवारों और पड़ोसियों के बीच वर्षों तक तनातनी बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भूमि विवाद किसी न किसी रूप में लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। पैतृक जमीन का बंटवारा, चकबंदी से जुड़ी विसंगतियां और सीमांकन की समस्याएं आम हैं। कई मामलों में पीढ़ियों से जमीन पर खेती कर रहे लोग अचानक खुद को विवादों में घिरा हुआ पाते हैं। इससे न सिर्फ उनकी आजीविका प्रभावित होती है, बल्कि मानसिक तनाव और सामाजिक तनाव भी बढ़ता है। भूमि विवादों का सीधा असर कानून-व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार, कई आपराधिक घटनाओं की जड़ में जमीन से जुड़ा विवाद ही पाया गया है। मारपीट, धमकी, आपसी रंजिश और लंबे कानूनी मुकदमे आम हो गए हैं। इससे पुलिस और प्रशासन पर भी अतिरिक्त दबाव बढ़ा है। अदालतों और तहसीलों में लंबित मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम आदमी को समय पर न्याय नहीं मिल पा रहा है। इन हालात को देखते हुए राज्य सरकार ने भूमि विवादों को गंभीर चुनौती के रूप में लेना शुरू किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर प्रशासन को साफ संदेश दिया गया है कि भूमि से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाया जाए। सरकार का मानना है कि जब तक जमीन के विवादों का समाधान नहीं होगा, तब तक आम लोगों की बड़ी समस्याएं बनी रहेंगी और विकास कार्यों पर भी असर पड़ेगा। प्रशासनिक स्तर पर यह भी माना जा रहा है कि भूमि विवादों की बढ़ती संख्या के पीछे जागरूकता की कमी और जटिल प्रक्रियाएं भी एक कारण हैं। कई लोग नियम-कानूनों की पूरी जानकारी के अभाव में गलत फैसले कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा उन्हें वर्षों तक भुगतना पड़ता है। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि विवादों का समाधान केवल कागजी नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर हो, ताकि लोगों को वास्तविक राहत मिल सके। देहरादून समेत राज्य के कई जिलों में बढ़ते भूमि विवाद उत्तराखंड के लिए एक गंभीर चुनौती बन चुके हैं। सरकार और प्रशासन की यह जिम्मेदारी बनती है कि इन मामलों का समयबद्ध, पारदर्शी और संवेदनशील तरीके से निस्तारण किया जाए। अगर ऐसा होता है, तो इससे न सिर्फ हजारों परिवारों को राहत मिलेगी, बल्कि राज्य में सामाजिक शांति और विकास का रास्ता भी और मजबूत होगा।

समझती है कि हर फाइल के पीछे किसी परिवार की कहानी, उसकी उम्मीदें और उसका संघर्ष छिपा होता है। धामी सरकार का यह कदम शासन-प्रशासन और जनता के बीच विश्वास को मजबूत करने की दिशा में भी अहम माना जा रहा है। जब आम आदमी को यह भरोसा मिलता है कि सरकार उसकी समस्या को गंभीरता से ले रही है और समयबद्ध समाधान दे रही है, तो लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत होती हैं। भूमि विवादों का त्वरित निस्तारण न केवल लोगों को राहत देगा, बल्कि राज्य में शांति, सामाजिक सौहार्द और विकास के माहौल को भी बढ़ावा देगा। भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण के लिए शुरू किया गया यह विशेष अभियान उत्तराखंड के लिए उम्मीद, राहत और न्याय का संदेश लेकर आया है। यह फैसला उन लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने जैसा है, जो सालों से अपनी जमीन और अपने हक के लिए भटक रहे थे। अगर यह अभियान अपने तय लक्ष्यों के अनुरूप सफल होता है, तो यह न केवल एक प्रशासनिक उपलब्धि होगी, बल्कि आम जनता के जीवन में वास्तविक बदलाव लाने वाला कदम साबित होगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित नववर्ष 2026 के कैलेंडर का किया विमोचन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में सूचना विभाग, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रकाशित नववर्ष 2026 के आधिकारिक कैलेंडर का विधिवत विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कैलेंडर के आकर्षक स्वरूप, उत्कृष्ट मुद्रण गुणवत्ता एवं विषयवस्तु की सराहना करते हुए कहा कि यह कैलेंडर राज्य सरकार की योजनाओं, उपलब्धियों तथा जनकल्याणकारी नीतियों के साथ-साथ सरकार द्वारा लिए गए ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी निर्णयों को प्रभावी ढंग से जनमानस तक पहुँचाने का सशक्त माध्यम है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित यह कैलेंडर केवल तिथियों का संकलन नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड की विकास यात्रा, प्रशासनिक प्रतिबद्धता एवं जनसेवा के संकल्प को दर्शाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है। कैलेंडर के माध्यम से राज्य सरकार के निरंतर प्रयासों को एक सुसंगठित एवं रचनात्मक रूप में प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री ने सूचना विभाग की टीम को इस उत्कृष्ट प्रकाशन के लिए बधाई देते हुए कहा कि विभाग ने सदैव सरकार और जनता के बीच सेतु की भूमिका निभाई है। उन्होंने अपेक्षा व्यक्त की कि भविष्य में भी सूचना विभाग नवीन तकनीकों, रचनात्मक सोच और नवाचार के साथ जनहितकारी सूचनाओं का व्यापक एवं प्रभावी प्रसार करता रहेगा, ताकि सरकार की योजनाओं और नीतियों की सही जानकारी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके। इस अवसर पर डीजी बंशीधर तिवारी, उपनिदेशक मनोज श्रीवास्तव एवं उत्तराखंड मीडिया सलाहकार समिति के अध्यक्ष गोविन्द सिंह उपस्थित रहे।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के बयान पर बवाल क्यों!

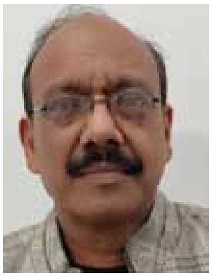
मनोज कुमार अग्रवाल

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल ने राजधानी दिल्ली में आयोजित 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' के उद्घाटन समारोह में युवाओं से कहा कि भारत को अपनी गुलामी हमलों और अधीनता के इतिहास का बदला लेना चाहिए लेकिन यह बदलाव सशक्त और महान भारत के पुनर्निर्माण के रूप में होना चाहिए। अब डोभाल के इसी संबोधन की कुछ लाइन व शब्दों को लेकर देश की विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने गंभीर आपत्ति और आलोचना शुरू कर दी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के इतिहास के लिए 'बदले' से जुड़े बयान पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि इस तरह की भाषा नफरत को बढ़ावा देती है और मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को सामान्य बनाने का काम करती है, जिससे एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी पर सवाल उठते हैं।

दरअसल, यह पूरा विवाद उस बयान के बाद सामने आया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने दिल्ली में 'विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग' के उद्घाटन समारोह में दिया था। अपने संबोधन में डोभाल ने कहा, 'आज का स्वतंत्र भारत हमेशा से उतना स्वतंत्र नहीं था, जितना अब दिखाई देता है। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने बड़े बलिदान दिए। उन्होंने गहरे अपमान सहे और लंबे समय तक बेबसी के दौर देखे। कई लोगों को फांसी पर चढ़ाया गया। हमारे गांव जलाए गए, हमारी सभ्यता को नष्ट किया गया, हमारे मंदिरों को लूटा गया और हम मूक दर्शक बनकर देखते रह गए। यह इतिहास आज के भारत के हर युवा के सामने एक चुनौती रखता है, जिसके भीतर यह आग होनी चाहिए।' अजित डोभाल ने कहा, 'बदला' शब्द शायद सही न लगे, लेकिन बदला अपने आप में एक बड़ी ताकत है। हमें अपने इतिहास के लिए बदला लेना होगा। हमें इस देश को उस स्थिति तक वापस ले जाना है, जहां हम अपने अधिकारों, अपने विचारों और अपने विश्वासों के आधार पर एक महान भारत का निर्माण कर सकें।

उन्होंने आगे कहा, 'हमारी सभ्यता बेहद विकसित थी। हमने कभी किसी के मंदिर नहीं तोड़े। हमने कहीं जाकर लूटपाट नहीं की। जब दुनिया का बड़ा हिस्सा बेहद पिछड़ा हुआ था, तब हमने किसी देश या किसी विदेशी लोगों पर हमला नहीं किया, लेकिन हम अपनी सुरक्षा और खुद पर मंडराते खतरों को समझने में असफल रहे। जब हम उनके प्रति उदासीन बने रहे, तब इतिहास ने हमें एक सबक सिखाया। क्या हमने वह सबक सीखा? क्या हम उस सबक को याद रखेंगे? अगर आने वाली पीढ़ियां उस सबक को भूल गईं, तो यह इस देश के लिए सबसे बड़ी त्रासदी होगी।'

इस यूथ सम्मिट में अजीत डोभाल ने कहा कि युद्ध राष्ट्र की इच्छाशक्ति के लिए लड़े जाते हैं। हम साइकोपैथ (मनोरोगी) नहीं हैं, जिन्हें दुश्मन के शव या कटे हुए अंग देखकर संतोष या सुकून मिले। लड़ाइयां इसके लिए नहीं लड़ी जाती। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी देश का मनोबल तोड़ने के लिए लड़े जाते हैं, ताकि वह हमारी शर्तों पर आत्मसमर्पण करें और हम अपने लक्ष्य हासिल कर सकें।

कार्यक्रम की शुरुआत में अजीत डोभाल ने बेहद सादगी और आत्मीयता के साथ युवाओं से खुद को जोड़ने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उनका कार्यक्षेत्र और अनुभव युवाओं से काफी अलग है और उम्र का अंतर भी बहुत बड़ा है। डोभाल ने कहा, ''आपमें से अधिकांश मुझसे 60 साल से ज्यादा छोटे हैं। मेरा जन्म स्वतंत्र भारत में नहीं, बल्कि आजादी से पहले हुआ था। मेरी जवानी तो कब की बीत चुकी है। इसलिए मैं यह सोचकर असमंजस में था कि यहां आऊं या नहीं।'' उन्होंने स्वीकार किया कि आज के बदलते दौर में तकनीक, सोच और जीवनशैली इतनी तेजी से बदल रही है कि वह सब कुछ जानने का दावा नहीं कर सकते, लेकिन कुछ मूल बातें ऐसी हैं, जो हर पीढ़ी को जोड़ती हैं।

युवाओं को संबोधित करते हुए एनएसए डोभाल ने निर्णय लेने की क्षमता को जीवन का सबसे अहम कौशल बताया। उन्होंने कहा कि चाहे समय बदले या तकनीक, इंसान के फैसले ही उसकी पहचान बनाते हैं। उनके शब्दों में, "एक छोटी सी बात है जो आपके पूरे जीवन की दिशा तय करती है, आपकी निर्णय लेने की क्षमता। आप रोज छोटे-बड़े फैसले लेते हैं। जैसे-जैसे आपकी उम्र और जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, फैसलों का महत्व और बढ़ता जाएगा।" डोभाल ने यह भी स्पष्ट किया कि भारत के भविष्य को लेकर उन्हें किसी तरह का संदेह नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि "भारत विकसित होगा, यह निश्चित है। इस पर कोई सवाल नहीं है।"

अपने संबोधन में अजीत डोभाल ने वैश्विक हालात और अंतरराष्ट्रीय संघर्षों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि दुनिया में चल रहे अधिकांश युद्ध और टकराव इस बात का नतीजा हैं कि कुछ देश दूसरों पर अपनी इच्छा थोपना चाहते हैं। डोभाल ने कहा, "अगर आप शक्तिशाली हैं, तो आप स्वतंत्र रहेंगे। लेकिन अगर आत्मविश्वास नहीं है, तो आपकी सारी शक्ति, हथियार और संसाधन बेकार हैं।" उन्होंने भारत के वर्तमान नेतृत्व की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश को ऐसा नेतृत्व मिलना सौभाग्य की बात है, जिसकी प्रतिबद्धता, समर्पण और कड़ी मेहनत पूरे राष्ट्र के लिए प्रेरणा है।

डोभाल ने नेतृत्व के महत्व को समझाने के लिए फ्रांस के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, "नेपोलियन ने एक बार कहा था, मैं एक भेड़ के नेतृत्व में 1000 शेरों से नहीं डरता, लेकिन एक शेर के नेतृत्व में 1000 भेड़ों से डरता हूं।" इस कथन के जरिए उन्होंने यह संदेश दिया कि नेतृत्व केवल पद या शक्ति का नाम नहीं है, बल्कि दिशा, आत्मविश्वास और साहस देने की क्षमता का नाम है।

विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में डोभाल ने इतिहास का उदाहरण देते हुए बताया कि भारत का वैश्विक नेतृत्व कोई नई बात नहीं है। उन्होंने 'विश्व अर्थव्यवस्था का इतिहास' नामक प्रसिद्ध पुस्तक का उल्लेख किया, जिसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने लिखा था। डोभाल के अनुसार, "जब जापान का उदय हो रहा था, तब पश्चिमी दुनिया में यह बहस शुरू हुई कि क्या कोई एशियाई देश पश्चिम से आगे निकल सकता है। इसी अध्ययन के तहत यह किताब लिखी गई।"

उन्होंने बताया कि इस पुस्तक में पहली से उन्नीसवीं शताब्दी तक का आर्थिक इतिहास दर्ज है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि करीब 1700 वर्षों तक भारत और कभी-कभी चीन विश्व अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करते रहे।

एनएसए ने कहा कि उस दौर में भारत और चीन मिलकर वैश्विक अर्थव्यवस्था का 55 से 60 प्रतिशत हिस्सा रखते थे। डोभाल ने कहा कि हम कभी विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था के शिखर पर थे। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि भारत का पतन हुआ, क्योंकि कोई भी सफलता स्थायी नहीं होती। यह एक निरंतर संघर्ष है। राष्ट्र को मजबूत बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास जरूरी है। यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता।

अपने भाषण के भावनात्मक हिस्से में अजीत डोभाल ने स्वतंत्रता संग्राम और शहीदों के बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि आज का भारत वैसा स्वतंत्र नहीं था जैसा आज दिखाई देता है। डोभाल ने कहा, "हमारे पूर्वजों ने अपमान सहे, बलिदान दिए और कई लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया। भगत सिंह को फांसी दी गई, सुभाष चंद्र बोस ने जीवन भर संघर्ष किया और महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का मार्ग दिखाया।" उन्होंने यह भी कहा कि अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वतंत्र भारत में सांस ले सकें।

एनएसए ने भारत के इतिहास के उन अध्यायों का भी जिक्र किया, जिनमें देश ने अपमान और अत्याचार सहे। उन्होंने कहा कि हमारे मंदिर तोड़े गए, गांव लूटे गए और हमारी सभ्यता को कुचल दिया गया, जबकि हम असहाय मूक दर्शक बने रहे। हालांकि डोभाल ने यह भी स्पष्ट किया कि इतिहास का उद्देश्य केवल दुख याद करना नहीं, बल्कि उससे सीख लेना है। इतिहास हमें चुनौती देता है।

अपने संबोधन के अंत में डोभाल ने युवाओं से आह्वान किया कि वे नकारात्मक भावना के बजाय सकारात्मक राष्ट्रनिर्माण की सोच अपनाएं। उन्होंने कहा, "बदला लेना अच्छा शब्द नहीं है, लेकिन यह शक्तिशाली भावना है। हमें अपने मूल्यों पर आधारित एक महान भारत का पुनर्निर्माण करके अपने देश का बदला लेना होगा।" डोभाल ने भरोसा जताया कि आज के युवाओं में वह जोश, क्षमता और आत्मविश्वास है, जो भारत को एक बार फिर वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जा सकता है। अब एनएसए के बयान की सिर्फ बदले वाले अधूरी लाइन को लेकर कुछ राजनीतिक विरोधी इस बयान के अपने मत अनुसार अलग अलग अर्थ निकाल कर हंगामा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वास्तव में अपने इतिहास को भुला कर बिना कोई सबक लिए हम सुरक्षित वर्तमान और विकसित संरक्षित भविष्य की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। हमें उनसे सबक लेकर ही भविष्य की तैयारी करनी होगी और एनएसए डोभाल भी शायद यही कहना चाहते हैं कि वह खून-खराबे वाले प्रतिशोध का नहीं बल्कि विकास और प्रगति के बल पर तरक्की का मूलमंत्र दे रहे हैं।

(विनायक फीचर्स)

स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग में उत्तराखंड को मिला 'लीडर' दर्जा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने प्रदान किया सर्टिफिकेट ऑफ एप्रीशीयेशन

भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी स्टेटस स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग (5वां संस्करण) में उत्तराखण्ड को मजबूत स्टार्टअप इकोसिस्टम विकसित करने में 'लीडर' के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। इस उपलब्धि के लिए राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड सरकार के उद्योग विभाग को सर्टिफिकेट ऑफ एप्रीशीयेशन प्रदान किया गया।

इस सम्मान से यह स्पष्ट होता है कि उत्तराखण्ड में स्टार्टअप नीति के जरिए नवाचार, उद्यमिता, निवेश प्रोत्साहन और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने में कामयाब रहा है, जिसे अब राष्ट्रीय स्तर पर सराहा जा रहा है। उत्तराखंड की उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर एक मॉडल के तौर पर भी देखा जा रहा है।

यह सम्मान उत्तराखण्ड के लिए गर्व का विषय है। हमारी सरकार ने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतियां, सरल प्रक्रियाएं और मजबूत इकोसिस्टम विकसित किया है। राज्य के युवाओं में नवाचार की अद्‌भुत क्षमता है और सरकार हर स्तर पर उन्हें सहयोग प्रदान कर रही है। यह उपलब्धि प्रदेश के सभी उद्यमियों, स्टार्टअप्स और अधिकारियों के सामूहिक प्रयास का परिणाम है।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री उत्तराखंड

दून डिफेंस एकेडमी ने अपने अग्निवीर छात्रों को किया सम्मानित

देश की प्रतिष्ठित रक्षा शिक्षण संस्थान, 'दून डिफेंस एकेडमी' ने एक बार फिर अपने नाम को सार्थक करते हुए भविष्य के योद्धाओं के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। एकेडमी के विजनरी निदेशक संदीप गुप्ता सर ने हाल ही में भारतीय नौसेना और वायुसेना में चयनित दो जांबाज *डीडीए डायमंड्स-विशाल राजपूत और हिमांशु जाट* के साथ एक विशेष पॉडकास्ट के माध्यम से संवाद किया और उनकी उपलब्धियों के लिए उन्हें सम्मानित किया।

आईएनएस चिल्का में गूंजा 'दून' का नाम: पॉडकास्ट के दौरान भारतीय नौसेना (बैच 01/2025) के लिए चयनित विशाल राजपूत ने एक दिलचस्प वाख्या साझा किया। विशाल ने बताया कि ट्रेनिंग सेंटर आईएनएस चिल्का में संदीप सर के साथ उनकी एक मुलाकात का वीडियो इतना वायरल हुआ कि वहां मौजूद उनके साथियों और अधिकारियों के बीच विशाल का नाम ही 'दून' पड़ गया। यह न केवल विशाल के लिए गर्व की बात है, बल्कि इस बात का प्रमाण भी है कि देश के हर कोने में डीडीए की साख कितनी मजबूत है।

संदीप गुप्ता सर का गुरुमंत्र और नकद पुरस्कार: अपने शिष्यों के समर्पण से गदगद संदीप गुप्ता सर ने विशाल और हिमांशु को रू10,000 की नकद राशि और स्मृति चिह्न भेंट कर सम्मानित किया। संदीप सर ने उन्हें भविष्य के लिए मार्गदर्शन देते हुए कहा, 'वर्दी पहनना सौभाग्य की बात है, लेकिन उस वर्दी की गरिमा बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। बुरी आदतों से दूर रहें और निरंतर अपनी शिक्षा को अपग्रेड करते रहें।

यूजेवीएन लिमिटेड की 132वीं बोर्ड बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी

यूजेवीएन लिमिटेड के निदेशक मंडल की 132वीं बोर्ड बैठक आज मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष यूजेवीएन लिमिटेड की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित की गई। बैठक में निदेशक मंडल द्वारा निगम के मानव संसाधन, परिचालन, परियोजनाओं एवं अन्य विषयों से जुड़े अनेक प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया।

निदेशक मंडल द्वारा निगम के स्थायी एवं अस्थायी पदों के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। निदेशक मंडल द्वारा के नई परियोजनाओं के तकनीकी आकलन एवं मार्गदर्शन हेतु विशेषज्ञ तकनीकी समूह के गठन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। यह समूह परियोजनाओं की तकनीकी व्यवहार्यता, डिजाइन तथा क्रियान्वयन से संबंधित सुझाव प्रदान करेगा। विशेषज्ञ तकनीकी समूह द्वारा सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में प्रस्तावित 114 मेगावॉट की सेला-उर्थिंग जलविद्युत परियोजना के साथ ही 102 मेगावॉट की मोरी-त्यूनी जलविद्युत परियोजना व अन्य परियोजनाओं पर भी आवश्यकतानुसार कार्य किया जाएगा। बैठक में मनेरी भाली द्वितीय चरण के जोशीयाड़ा बैराज के डाउनस्ट्रीम में जल प्रवाह को न्यूनतम करने से संबन्धित कार्यों की संशोधित लागत एवं प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को भी पारित कर दिया गया। निदेशक मंडल द्वारा मोरी त्यूनी परियोजना हेतु परामर्शदात्री सेवाएं लेने के प्रस्ताव पर भी सहमति जताई गई। इसी क्रम में 300 मेगावॉट क्षमता वाली लखवाड़ परियोजना के विद्युत यांत्रिक कार्यों हेतु अद्यतन लागत व संशोधित प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव को भी बैठक में स्वीकृति प्रदान की गई। चमोली जनपद में स्थित 3 मेगावॉट क्षमता वाली उर्गम लघु जल विद्युत परियोजना के पुनरोद्धार हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट व निवेश योजना के प्रस्ताव को भी बैठक में अनुमोदित कर दिया गया। 72 मेगावाट की त्यूनी प्लासु परियोजना में विद्युत यांत्रिक उपकरणों की स्थापना हेतु निविदा आमंत्रित करने के प्रस्ताव को भी निदेशक मंडल द्वारा स्वीकृत कर दिया गया। पिथौरागढ़ जनपद में श्यामखोलागाड़ नदी पर 12 मेगावॉट की तांकुल परियोजना के सिविल डिजाइन व इंजीनियरिंग हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई। निदेशक मंडल ने उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग के 2025 विनियमों में बैटरी आधारित ऊर्जा भंडारण टैरिफ व ट्रेडिंग मार्जिन संबंधी प्रावधानों पर समीक्षा याचिका दायर करने की अनुमति भी प्रदान की। बैठक में मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन एवं अध्यक्ष यूजीवीएन लिमिटेड आनंद वर्धन, प्रमुख सचिव ऊर्जा डॉ. आर. मिनाक्षी सुंदरम, सचिव वित्त दिलीप जावलकर के साथ ही इंदु कुमार पांडेय, बी.पी. पांडेय, पराग गुप्ता, यूजेवीएन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक डॉ. संदीप सिंघल, आदि अधिकारी उपस्थित रहे।

शीतकालीन पर्यटन सम्मेलन औपचारिकता नहीं, उत्तराखंड को 12 महीने का टूरिज्म स्टेट बनाने का साझा प्रयासः मुख्यमंत्री

उत्तराखंड बनेगा देश का 'नेचुरल हीलिंग डेस्टिनेशन, चारधाम के अलावा वेलनेस व एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावनाएं

शीतकालीन चारधाम यात्रा एवं पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा स्थानीय लोगों को वर्षभर रोजगार से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल के तहत तीन दिवसीय विंटर टूरिज्म कॉनक्लेव का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया।

कॉनक्लेव में एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया के सहयोग से देश के विभिन्न राज्यों से आए 50 टूर ऑपरेटर्स ने प्रतिभाग किया। इसके अतिरिक्त राज्य स्तर से 50 तथा स्थानीय स्तर से भी 50 टूर ऑपरेटर्स ने कॉनक्लेव में भाग लिया। कार्यक्रम में होटल एसोसिएशन उत्तरकाशी एवं बड़कोट, ट्रैकिंग संगठन उत्तरकाशी और सांकरी के पंजीकृत प्रतिनिधियों की भी सक्रिय सहभागिता रही। निम में आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से शीतकालीन पर्यटन की संभावनाओं पर मंथन किया गया तथा उत्तराखंड को वर्षभर पर्यटन गंतव्य के रूप में विकसित करने पर जोर दिया गया। तीन दिवसीय विंटर टूरिज्म कॉन्क्लेव के तहत मां गंगा का शीतकालीन प्रवास मुखबा एवं मां यमुना का खरसाली तथा सांकरी में केदारकांठा ट्रैक बेस केम्प का देश भर के टूर ऑपरेटर भ्रमण करेंगे तथा शीतकालीन टूरिज्म को बढ़ावा देंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विंटर टूरिज्म कान्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि शीतकालीन पर्यटन सम्मेलन केवल एक औपचारिक संवाद नहीं,बल्कि उत्तराखंड के पर्यटन को नई दिशा देने का एक साझा प्रयास है। उन्होंने टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवल एजेंट्स, होटल व्यवसायियों, होम-स्टे संचालकों, टैक्सी एवं ट्रांसपोर्ट यूनियन के प्रतिनिधियों, एडवेंचर टूरिज्म से जुड़े लोगों का स्वागत और उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज देश के बड़े शहर प्रदूषण, बढ़ते तापमान, ट्रैफिक और तनाव से जूझ रहे हैं। ऐसे में उत्तराखंड देश का एक "नेचुरल हीलिंग डेस्टिनेशन" बन सकता है और सरकार इसी दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अब केवल चारधाम यात्रा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वेलनेस, नेचर, एडवेंचर, कल्चर, योग, मेडिटेशन और सस्टेनेबल टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ने टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि ट्रेंड बनाना और किसी डेस्टिनेशन को ब्रांड बनाना आप सभी के हाथ में है। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि उत्तराखंड को केवल 4 या 6 महीने का नहीं, बल्कि 12 महीने का टूरिज्म स्टेट बनाया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार की शीतकालीन पर्यटन नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पहाड़ खाली न रहें, होटल बंद न हों, टैक्सियां खड़ी न रहें, होमस्टे सूने न रहें और युवाओं को रोजगार के लिए पलायन न करना पड़े। जब 12 महीने पर्यटन सक्रिय रहेगा तो प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी व्यापक सुधार होगा।

मुख्यमंत्री ने टूरिज्म से जुड़े सभी हितधारकों से संवाद करते हुए कहा कि चाहे परमिशन हो, कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर या मार्केटिंग सपोर्ट-सरकार हर स्तर पर सहयोग के लिए तैयार है। इसके साथ ही पर्यटन विभाग के माध्यम से सिंगल विंडो सिस्टम, डिजिटल अप्रूवल और निवेशकों के लिए फास्ट-ट्रैक सपोर्ट को और मजबूत किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन का अर्थ केवल बड़े होटल नहीं,बल्कि जब गांव की महिला का होमस्टे भरे, स्थानीय युवा टैक्सी चलाएं, पहाड़ी युवक ट्रेकिंग गाइड बनें, लोक कलाकारों को मंच मिले और किसान के उत्पाद सीधे पर्यटक तक पहुंचें-तभी पर्यटन सार्थक होगा। इसी उद्देश्य से सरकार ने होमस्टे नीति को सरल बनाया है, लखपति दीदी योजना से महिलाओं को जोड़ा है, लोकल गाइड ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किए हैं और "वोकल फॉर लोकल" को पर्यटन से जोड़ा है। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण और संस्कृति पर जोर देते हुए कहा कि सरकार विकास चाहती है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण, स्थानीय संस्कृति का संरक्षण और गांव के अंतिम व्यक्ति को पर्यटन से जोड़ना ही सरकार का रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मॉडल है। उन्होंने सभी टूर ऑपरेटर्स से आग्रह किया कि वे अपने पर्यटन पैकेज में उत्तरकाशी, हर्षिल, मुखबा, नेलांग, चमोली, औली, मुनस्यारी, पिथौरागढ़, चम्पावत, टिहरी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग एवं सीमांत गांवों को शामिल करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप पैकेज बनाइए, सरकार आपके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने युवाओं और निवेशकों को संदेश देते हुए कहा कि उत्तराखंड निवेश के लिए पूरी तरह तैयार है, क्योंकि यहां पर्यटन केवल व्यवसाय नहीं, बल्कि रोजगार का सबसे बड़ा इंजन है। उन्होंने कहा कि होटल मालिक, होमस्टे संचालक, टैक्सी चालक और ट्रैवल एजेंट-सभी को काम मिले और हर गांव को पहचान मिले, यही सरकार का लक्ष्य है। इस अवसर पर गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान, पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल, दर्जा राज्य मंत्री रामसुंदर नौटियाल,जगत सिंह चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा डॉ.स्वराज विद्वान, प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान, गढ़वाल समन्वयक किशोर भट्ट,जिलाध्यक्ष भाजपा नागेंद्र चौहान, पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण,डीएम प्रशान्त आर्य, एसपी कमलेश उपाध्याय, सीडीओ जयभारत सिंह, रजिस्ट्रार निम विशाल रंजन, जिला पर्यटन विकास अधिकारी केके जोशी सहित अन्य अधिकारी एवं जनप्रतिनिधिगण उपस्थित रहे।

डॉ. नरेश बंसल ने सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए

डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में एक नई खेल संस्कृति विकसित हुई है। आज देहरादून के परेड ग्राउंड मे चल रहे सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के दूसरे दिन पुरस्कार वितरण कार्यक्रम मे डा. नरेश बंसल ने कहा कि केंद्र और उत्तराखंड प्रदेश सरकारों ने खेल-अनुकूल नीतियां अपनाई हैं। इसके परिणामस्वरूप, छोटे शहरों के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिल रहा है। डा. नरेश बंसल ने कहा कि सरकार 2036 में गुजरात में होने वाले ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, साथ ही भारत में अन्य विश्व स्तरीय खेलों के आयोजन के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी के परिणाम आने वाले वर्षो में स्पष्ट रूप से दिखाई देंगे, जब देहरादून समेत राज्य व देश के युवा खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी संख्या में पदक जीतेंगे। सांसद चैंपियनशिप के समापन अवसर पर डॉ. नरेश बंसल ने कहा कि इस तरह की खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन से ग्रामीण अंचल की प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। उन्होंने विशेष रूप से छात्राओं से खेलों में बढ़-चढ़कर प्रतिभाग करने का आहवान किया। समारोह के दौरान डा. नरेश बंसल ने वरिष्ठ एथलीटों, कोचों के साथ-साथ खेल प्रबंधन पेशेवरों को सम्मानित किया एवं विजेता खिलाडियो को पुरस्कार

दिए। प्रतियोगिता के दौरान अंडर-19 वर्ग व अंडर-14 वर्ग की कई खेल स्पर्धाओं का आयोजन किया गया, जिनमें खिलाड़ियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

अण्डर 14 बालिका खो-खो प्रतियोगिता का फाइनल मैच विधानसभा रायपुर तथा विकासनगर की टीमों के मध्य खेला गया जिसमें विकासनगर की टीम ने 5-2 से जीत दर्ज कर प्रथम स्थान प्राप्त किया।

प्रतियोगिता में तीसरे स्थान के लिए विधानसभा चकराता एवं मसूरी के मध्य खेले गए मुकाबले में मसूरी ने 4-2 से जीत दर्ज की।

अण्डर 14 बालक खो-खो प्रतियोगिता में विधानसभा रायपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान विधानसभा चकराता तथा तीसरा स्थान विधानसभा सहसपुर ने प्राप्त किया।

अण्डर 19 बालिका रिले दौड़-

प्रतियोगिता में प्रथम स्थान विधानसभा सहसपुर की टीम (कु० इकरा, कु० सहाना, कु० सलोनी तथा कु० सानिया) ने प्राप्त किया।

प्रतियोगिता में द्वितीय स्थान विधानसभा रायपुर की टीम (कु० सताक्षी, कु० मनीषा, कु० रितिका तथा कु० सृष्टि ठाकुर) ने प्राप्त किया।

अण्डर 19 बालिका 3000 मीटर दौड़-

प्रतियोगिता में प्रथम स्थान विधानसभा विकासनगर की नीलम ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान विधानसभा राजपुर की वैष्णवी तथा तीसरा स्थान विधानसभा चकराता की तन्नु ने प्राप्त किया।

अण्डर 19 बालक 5000 मीटर दौड़-

प्रतियोगिता में प्रथम स्थान विधानसभा रायपुर के आकाश कुमार ने प्राप्त किया। द्वितीय स्थान विधानसभा राजपुर के रोहित तथा तीसरा स्थान विधानसभा चकराता के जयवीर ने प्राप्त किया।

अण्डर 14 बालक वालीबाल प्रतियोगिता में विधानसभा सहसपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। द्वितीय स्थान विधानसभा रायपुर तथा तीसरा स्थान विधानसभा चकराता ने प्राप्त किया।

इस अवसर पर भाजपा नेता प्रमोद चौधरी, रोमा सैनी, सिद्धार्थ बंसल, जिला युवा कल्याण अधिकारी श्री प्रमोद पाण्डे जी, जिला क्रीड़ा अधिकारी रविन्द्र भंडारी जी आदि संबंधित अधिकारीगण, कोच व खिलाड़ी उपस्थित रहे।

जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार कार्यक्रम में रिकॉर्ड उपलब्धिः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लाखों लोगों को मिला त्वरित समाधान

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेशभर में संचालित "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" कार्यक्रम ने जनसेवा, पारदर्शिता और त्वरित समाधान के क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। आज 16 जनवरी 2026 तक आयोजित शिविरों के आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि राज्य सरकार आमजन की समस्याओं को उनके द्वार तक जाकर सुनने और समाधान देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अब तक कुल 363 शिविर आयोजित किए गए, जिनमें से 347 शिविर पूर्व दिवसों तक और 16 शिविर आज आयोजित हुए। इन शिविरों के माध्यम से कुल 2,80,030 नागरिकों ने सहभागिता की, जिनमें 2,77,654 लोग पूर्व दिवसों तक और 10,376 लोग आज शामिल रहे। यह दर्शाता है कि सरकार की इस पहल को जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है।शिविरों में प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक कुल 29,086 शिकायतों का निस्तारण किया गया है, जिनमें 28,293 शिकायतें पूर्व दिवसों तक तथा 793 शिकायतों का निस्तारण आज किया गया। इसके साथ ही कुल 19,491 शिकायतें पंजीकृत की गईं, जिनमें 18,973 शिकायतें पूर्व दिवसों तक और 518 शिकायतें आज दर्ज की गईं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रत्येक शिकायत को गंभीरता से लिया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री धामी की मंशा के अनुरूप शिविरों में प्राप्त आवेदनों के समर्थन में विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र भी बड़ी संख्या में बनाए गए। कार्यक्रम के अंतर्गत अब तक कुल 39,689 प्रमाण पत्र तैयार किए गए, जिनमें 38,255 प्रमाण पत्र पूर्व दिवसों तक और 1,444 प्रमाण पत्र आज बनाए गए। यह सुविधा नागरिकों के लिए प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और सुलभ बना रही है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न सरकारी योजनाओं से लाभान्वित किए गए नागरिकों की संख्या भी उल्लेखनीय रही। कार्यक्रम के माध्यम से अब तक कुल 1,58,239 व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया, जिनमें 1,59,565 लाभार्थी पूर्व दिवसों तक और 6,674 लाभार्थी आज शामिल हैं। यह उपलब्धि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के प्रभावी क्रियान्वयन को दर्शाती है।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि "जन-जन की सरकार, जन-जन के द्वार" कार्यक्रम का उद्देश्य केवल समस्याएं सुनना नहीं, बल्कि उनका त्वरित और प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जनता से प्राप्त प्रत्येक शिकायत और सुझाव पर संवेदनशीलता और पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाए, ताकि शासन और जनता के बीच विश्वास और अधिक मजबूत हो। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यह कार्यक्रम उत्तराखंड में सुशासन का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा है, जिसने प्रशासन को सीधे जनता से जोड़ते हुए सेवा, समाधान और संतुष्टि की नई मिसाल कायम की है।

नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तराखंड अव्वल

नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में उत्तराखंड ने छोटे राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर देशभर में अपनी मजबूत पहचान बनाई है। यह उपलब्धि राज्य की निर्यातोन्मुख नीतियों, बेहतर कारोबारी माहौल और सुदृढ़ बुनियादी ढांचे का परिणाम मानी जा रही है।

सीएम धामी ने दी प्रदेशवासियों को बधाई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि नीति आयोग के निर्यात तैयारी सूचकांक 2024 में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड का शीर्ष स्थान प्राप्त करना राज्य के लिए गर्व का विषय है। यह हमारी सरकार की उद्योग समर्थक नीतियों, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और निर्यात को बढ़ावा देने की सतत कोशिशों का परिणाम है। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड के प्रत्येक जिले के विशिष्ट उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई जाए, जिससे रोजगार के अवसर बढ़ें और राज्य की अर्थव्यवस्था और सशक्त हो।

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार, निर्यात आर्थिक विकास का प्रमुख इंजन है। इससे न केवल विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, बल्कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में भागीदारी बढ़ती है और व्यापार घाटे को कम करने में मदद मिलती है।

उत्तराखंड का यह शीर्ष स्थान राज्य को निवेश और औद्योगिक विकास के नए अवसरों की ओर ले जाने वाला कदम माना जा रहा है।

रचनात्मकता बालिकाओं को निर्भिक और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करती हैः कुमकुम रानी

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की अध्यक्षा कुमकुम रानी ने किया 17 बालिकाओं की लिखी कहानियों के संग्रह का विमोचन

उदयन केयर द्वारा संचालित उदयन शालिनी फेलोशिप, देहरादून चैप्टर के तत्वावधान में बाल एवं किशोर लेखिकाओं द्वारा लिखित कहानी-संग्रह “शाम-सवेरे” पुस्तक का लोकार्पण समारोह दून लाइब्रेरी एंड रिसर्च सेंटर, देहरादून में आयोजित हुआ। यह पुस्तक शालिनियों की भावनाओं, अनुभवों, संघर्षों और रचनात्मक सोच का सशक्त संकलन है, जिसमें 17 शालिनियों द्वारा लिखी गई लघु कहानियाँ शामिल हैं, जो आत्मनिर्भरता, साहस, मानवीय संवेदना, संबंधों, संघर्ष और आशा जैसे विषयों को उजागर करती हैं।

समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उत्तराखंड कुमकुम रानी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ पत्रकार, कवि एवं लेखक वीरेंद्र डंगवाल 'पार्थ' की गरिमामयी उपस्थिति रही।

मुख्य अतिथि कुमकुम रानी ने अपने संबोधन में कहा कि “शाम-सवेरे'' में संकलित कहानियाँ शालिनियों के आत्मविश्वास, संवेदनशील सोच और जीवन के यथार्थ को सरल, प्रभावी और सार्थक रूप में प्रस्तुत करती हैं। ऐसी रचनात्मक पहल बालिकाओं को अपनी बात निर्भीकता से रखने, पढ़ने-लिखने की आदत विकसित करने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में प्रेरित करती है। उन्होंने पुस्तक की कहानियों से उद्धरणों का उदाहरण देते हुए कहा कि इन्हें पढ़ते हुए जीवन का यथार्थ सामने आ जाता है। कुमकुम रानी ने उदयन शालिनी फैलोशिप की इस पहल की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि भविष्य में और अधिक शालिनियां लेखन क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अपने अनुभव और ज्ञान से अन्य के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगी।

विशिष्ट अतिथि वीरेंद्र डंगवाल 'पार्थ' ने अपने संबोधन में कहा कि यह कहानी-संग्रह दर्शाता है कि शिक्षा केवल अकादमिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं, बल्कि विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज को समझने की क्षमता भी देती है। उन्होंने कहा कि ये कहानियाँ पढ़ने से स्पष्ट होता है कि नई पीढ़ी संवेदनशील, विचारशील एवं सामाजिक मुद्दों के प्रति जागरूक है। वीरेंद्र डंगवाल श्पार्थश ने बालिकाओं को नियमित लेखन और पठन जारी रखने हेतु प्रेरित करते हुए कहा कि साहित्य की इस यात्रा में वे हरसंभव सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

उदयन शालिनी फैलोशिप देहरादून चैप्टर के संयोजक विमल डबराल ने कहा कि “शाम-सवेरे” केवल एक पुस्तक नहीं, बल्कि युवा लेखिकाओं की साहित्यिक यात्रा की एक सशक्त शुरुआत है, जो भविष्य में और भी रचनात्मक उपलब्धियों के साथ जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि शालिनियों के साथ साथ संस्था का भी यह प्रथम प्रयास था जो कि जो कि अल्प समय में पूर्ण किया गया। विमल डबराल ने कहा कि प्रत्येक कहानी किसी न किसी रूप में हमारे जीवन, समाज और हमारे इर्द-गिर्द घटती घटनाओं से जुड़ी है। कार्यक्रम में पुस्तक से जुड़ी शालिनियों ने भी अपने विचार तथा कहानी लेखन के अपने अनुभव साझा किए। निकिता ने अपनी कहानी को आत्मनिर्भरता और साहस, जाहिदा ने परिवार से दूर रहकर मजबूत बनने, सुहानी ने मेहनत और विश्वास, अजमतुल बानो ने मानवीय संवेदना और करुणा, स्वाति ने बचपन की मासूमियत, साजिया ने संघर्षों के बीच साहस और आशा तथा साक्षी ने जीवन की भावनात्मक सच्चाइयों को अपनी कहानियों के माध्यम से सशक्त रूप से प्रस्तुत किया।

कार्यक्रम में उदयन शालिनी फेलोशिप, देहरादून चैप्टर के संयोजक विमल डबराल, सह-संयोजक जी.एस. रावत कोर कमेटी सदस्य डॉ. दलजीत कौर, नीलू खन्ना, कमल शर्मा, सुमन तिवारी, दीपक अहलावत, ममता अहलावत, भोम बहादुर पुन, रुचिता नैथानी, विजय आईजैकर सहित अन्य गणमान्य अतिथि, दून लाइब्रेरी के सदस्य तथा बड़ी संख्या में साहित्यप्रेमी आदि उपस्थित रहे।

इनकी छपी हैं कहानियां

निशिता कश्यप, निशा कुमारी, नीलम जैस्वाल, रियाल, स्वाति, साक्षी पांडे, साजिया समीम मलिक, सुहानी यादव,अंजली माइकल, अजमतुल बानो, इकरा अंसारी, इरम, कंचन राणा, खुशी चौहान, चेतना नेगी, ज्योति गौतम, जाहिदा शेख।

जानिए कैसा होगा आपका यह सप्ताह

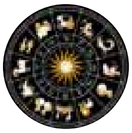
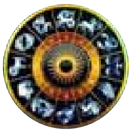
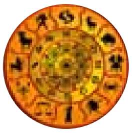

पं. दीपक प्रसाद, शास्त्री (मो. 9557730042)
(ज्योतिष, कर्मकाण्ड, धर्मिक अनुष्ठान आदि)

मेष राशि- व्यवसाय में छोटी समस्याएं बनी रह सकती हैं। दूसरों की सलाह आपको उलझा सकती है। ऑफिस में उच्च अधिकारियों से संबंध सही रखेंगे तो लक्ष्य हासिल हो सकता है। वरिष्ठों के स्नेह और मार्गदर्शन से घर का माहौल शांत रहेगा। प्रदूषण और सर्दी से खुद को बचाये। चिंता की बात नहीं। दिनचर्या व्यवस्थित रखें। भाग्यशाली रंग- पीला, भाग्यशाली अंक- 3

वृषभ राशि- काम को नया रूप देने के लिए रचनात्मक तरीके अपनाएंगे और सफलता मिलेगी। संतान की किसी गतिविधि को लेकर चिंता हो सकती है। अनुभवी व्यक्ति की सलाह ले। कोर्ट केस का मामला आपसी सहमति से सुलझ सकता है। मनपसंद कामों के लिए समय निकालें। थकान और तनाव से कमजोरी रह सकती है। भाग्यशाली रंग- नारंगी, भाग्यशाली अंक- 8

मिथुन राशि- प्रॉपर्टी का कोई मामला सुलझ सकता है। रुकी पेमेंट मिलने की उम्मीद है। नकारात्मक स्थिति बने तो समय के साथ समझौता न करें। बिना सोचे जल्दबाजी में निर्णय न लें। मानसिक स्थिति को सकारात्मक रखे। मीडिया और कम्युनिकेशन से जुडे कामों में निर्णय लेते समय सतर्क रहें। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 4

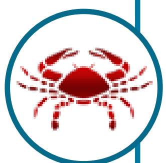

कर्क राशि- कोई भी अहम निर्णय लेने से पहले सभी पहलुओं पर सोचें। जल्दबाजी नुकसान करा सकती है। घरेलू विवादों को तूल न दें और संयम से सुलझाएं। कुछ रुकावटें रह सकती हैं, पर बाद में लाभदायक स्थिति बनेगी। सेल-परचेज से जुडे लोगों की कोई डील हो सकती है। ऑफिस में पेपरवर्क में सावधानी रखें। भाग्यशाली रंग- बादामी, भाग्यशाली अंक- 9

सिंह राशि- जमीन से जुडे रुके काम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरों के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप न करें। घर में मांगलिक आयोजन की योजना बनेगी और परिवार साथ देगा। प्रेम संबंध भी मजबूत होंगे। स्वास्थ्य- अधिक मेहनत से थकान और दर्द हो सकता है। मौसम के अनुसार दिनचर्या और खानपान रखें। भाग्यशाली रंग- केसरिया, भाग्यशाली अंक- 3

कन्या राशि- विद्यार्थियों को पढाई पर ज्यादा ध्यान देना होगा। पार्टनरशिप में अनबन की आशंका है और लेबर से परेशानी हो सकती है। शांति से समाधान निकालें। सरकारी नौकरी वालों के लिए उन्नति के योग हैं। पति-पत्नी का भरोसा रिश्तों को मजबूत रखेगा। महिलाओं को स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी में लापरवाही न करें। भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 5

तुला राशि- मनोरंजक यात्रा का प्लान बन सकता है। किसी अप्रिय व्यक्ति के आने से माहौल तनावपूर्ण हो सकता है, जिसका असर काम पर भी पडेगा। जरूरी काम समय रहते निपटाएं। कार्यस्थल पर अभी बदलाव करना ठीक नहीं है। निवेश से पहले अनुभवी की सलाह लें। ऑफिस में किसी सहयोगी से मनमुटाव हो सकता है। भाग्यशाली रंग- सफेद, भाग्यशाली अंक- 2

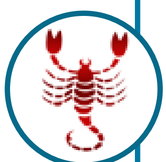

वृश्चिक राशि- योजनाओं को सही तरीके से लागू करना लाभकारी रहेगा। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें। दूसरों से उम्मीद ना रखे। कुछ लोग रुकावट डाल सकते हैं। काम और परिवार के बीच तालमेल बैठाना चुनौती रहेगा। लेनदेन में सावधानी रखें और सोच-विचार में ज्यादा समय न गंवाएं। पेपर और फाइलें पूरी रखें। भाग्यशाली रंग- गुलाबी, भाग्यशाली अंक- 4

धनु राशि- वरिष्ठ सदस्य की सेहत के कारण दिनचर्या बिगड़ सकती है। टैक्स से जुड़ा मामला उलझ सकता है, पर सरकारी व्यक्ति की मदद से समाधान मिल सकता है। मेहनत का फल निकट भविष्य में मिलेगा। कोई ऑफिशियल यात्रा रद्द हो सकती है। परिवार में सुख-शांति रहेगी। घर में बच्चे से जुड़ी शुभ सूचना मिलेगी। भाग्यशाली रंग- लाल, भाग्यशाली अंक- 9

मकर राशि- युवाओं को इंटरव्यू में सफलता की उम्मीद है। ज्यादा सोच-विचार से अवसर निकल सकता है, इसलिए सही समय पर निर्णय लें। प्रॉपर्टी में अच्छी डील हो सकती है। सरकारी नौकरी वालों को महत्वपूर्ण अथॉरिटी मिल सकती है। सिर दर्द और माइग्रेन से राहत के लिए खानपान और दिनचर्या व्यवस्थित रखें। भाग्यशाली रंग- नीला, भाग्यशाली अंक- 1

कुंभ राशि- ज्यादा संवेदनशील होना नुकसान दे सकता है। अपरिचित लोगों पर भरोसा न करें। अपनी नकारात्मक बातों पर नियंत्रण रखेंगे तो स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी। मशीनरी और तेल से जुड़ा कारोबार मुनाफा दे सकता है। ऑफिशियल काम समय पर पूरे करें। बाहरी व्यक्ति की वजह से गलतफहमी बन सकती है। भाग्यशाली रंग- हरा, भाग्यशाली अंक- 6

मीन राशि- घरेलू मामलों को सुलझाने में किसी शुभचिंतक की सलाह मदद करेगी। आर्थिक स्थिति ज्यादा अनुकूल नहीं है, क्षमता से अधिक खर्च न करें। कर्ज या लोन लेने की योजना हो तो पुनर्विचार करें। पति-पत्नी के सामंजस्य से घर में खुशी रहेगी। विवाह योग्य लोगों के लिए अच्छे रिश्ते आ सकते हैं। भाग्यशाली रंग- आसमानी, भाग्यशाली अंक- 7

R.N.I.: UTTHIN/2010/41629 | Postal Regd. UA/DO/DDN/01/2025-2027

Silkyara™

Pahad ki Mahilaon Dwara Banaya Gaya

Pure & Natural

A2 Badri Cow Ghee

A2 Beta Protein

Bilona Method

Immunity Booster

fssai 22623030001586

UDYOG AADHAR MSME UK050061483

THE DOON HIMALAYAN AGRO FOODS
Dalanwala, Dehradun
Customer Care - 7409782771

Available at

KUMAR SWEETS
Sahastradhara Road,
Near Crossing, Dehradun
7017180869

PLANET JR
Panditwadi,
Chakrata Road, Dehradun
9897477151